वर्ष 13 • अंक 6 • 10 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 22 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

सोने के दामों में 2 फीसदी उछाल

दिलीप सांघवी ▶▶ पृष्ठ 2

सन फार्मा ने तोड़े नियम : सेबी

एक नज़र

महाशिवरात्रि पर बंद रहे शेयर और जिंस बाजार

महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और मुद्रा विनिमय बाजार में अवकाश रहा। इसके साथ ही सराफा और प्रमुख थोक बाजारों में भी कारोबार नहीं हुआ।

खुल्बे और सिन्हा बने प्रधानमंत्री के सलाहकार

सेवानिवृत आईएएस अधिकारी भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों 1983 बैच के आईएएस हैं। खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर और सिन्हा बिहार कैडर के थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी नियुक्ति दो साल के लिए की गई है।

इंडियन बैंक के एटीएम से 2,000 रुपये के नोट नहीं

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने अपनी शाखाओं को एटीएम और कैश रिसाइक्लर में 2,000 रुपये का नोट नहीं भरने को कहा है। बैंक का कहना है कि उपभोक्ताओं को बड़े नोट का छुट्टा कराने में परेशानी हो रही है। बैंक के डिजिटल बैंकिंग डिवीजन के 17 फरवरी के परिपत्र के मुताबिक 1 मार्च से एटीएम और कैश रिसाइक्लर में 2,000 रुपये के नोट से संबंधित कैसेट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पृष्ठ 4

प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन का मसौदा किया सार्वजनिक

सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून में कई तरह के बदलाव का प्रस्ताव किया है। इनमें संबंधित पक्षों के उन मामलों के निपटान की मांग का प्रावधान भी शामिल है, जिन्हें लेकर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हों। प्रतिस्पर्धा कानून 2002 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक का मसौदा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसमें कई बदलावों के सुझाव मिलने के छह महीने बाद सार्वजनिक किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार इस विधेयक में मामलों के निपटान के प्रावधान समेत कई प्रस्ताव दिए गए हैं।

डीएचएफएल के वधावन को मिली जमानत

दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन को इकबाल मिर्ची से जुड़े एक मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने 27 जनवरी को वधावन को गिरफ्तार किया था। वधावन ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए जमानत अर्जी दायर की कि मिर्ची की संपत्तियों से जुड़े सौदे में उनका कोई संबंध नहीं है।

एफएटीएफ ने पाक को ग्रे सूची में ही रखा

वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने शुक्रवार को पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखने का फैसला किया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को धन देना बंद नहीं करता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पेरिस में चल रहे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के पूर्ण सत्र में यह फैसला किया गया।

ट्रंप के रुख से पहेली बना व्यापार समझौता

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 21 फरवरी

- व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप ने दिए अलग-अलग बयान
- अधिकारियों को किसी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर की नहीं है उम्मीद
- कृषि उत्पादों से जुड़े कुछ छोटे व्यापारिक सौदे पर करार संभव

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में शुक्रवार को विरोधाभासी बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इससे हर कोई यह अनुमान लगा रहा है कि उनके अगले सप्ताह होने वाले भारत दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे या नहीं।

ट्रंप ने पहले लास वेगस में संकेत दिया कि उनके भारत दौरे में एक शानदार समझौता हो सकता है। लेकिन एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने साथ ही कहा कि इस पर दोनों देशों की रफ्तार कम हो सकती है। हम चुनाव के बाद इसे अंजाम देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन बाद में उन्होंने कोलाराडो में एक चुनावी जनसभा में भारत के प्रति सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि वह कई सालों से ज्यादा शुल्क लगाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी उत्पादों को बढ़ावा देने, खासकर भारत में उन पर लगने वाले शुल्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां अमेरिकी उत्पादों पर सबसे अधिक शुल्क लगता है।

ट्रंप का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी और भारत विवादास्पद बातचीत पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है।

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उनके भारत दौरे में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीद नहीं है। उनका कहना था कि भारत के साथ व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने में समय लगेगा। भारत का भी कहना है कि ट्रंप के दौरे में बातचीत रक्षा सहयोग बढ़ाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और एच1बी वीजा को लेकर भारत की चिंता पर केंद्रित रहेगी।

हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत छोटे व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद कर रहा है, जो कृषि उत्पादों से जुड़े हो सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'अमेरिका बड़े सौदे करना चाहता है, जैसा कि इस साल की शुरुआत में चीन के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए किए गए थे। लेकिन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइज़र का नई दिल्ली का दौरा अचानक रद्द होने से व्यापार को लेकर बातचीत एकदम से बंद हो गई है।'

लाइटहाइज़र को व्यापार के लिए ट्रंप का खास माना जाता है और विश्व व्यापार संगठन में लंबी लड़ाई के बाद पिछले साल भारत के निर्यात संवर्द्धन योजना का अधिकांश हिस्सा बंद करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि हालांकि कृषि को लेकर बातचीत की राह अभी खुली है और दोनों देशों के प्रमुखों के संयुक्त बयान में व्यापार सहयोग संधि की सीमित घोषणा की जा सकती है। इसके तहत बादाम, अखरोट, सेब और शराब जैसे उच्च मूल्य के उत्पादों के आयात पर शुल्क को भारत रणनीतिक तौर पर कम कर सकता है। पिछले साल सरकार ने जिन 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क में 50 फीसदी का इजाफा किया था, उनमें ये कृषि उत्पाद भी शामिल हैं।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 10

बिज़नेस स्टैंडर्ड- सीमा नाज़रेथ अवार्ड

फोटो: दलीप कुमार

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार (बीच में) ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के युवा पत्रकार शुभायन चक्रवर्ती (दाएं) को बिज़नेस स्टैंडर्ड सीमा नाज़रेथ अवॉर्ड तथा वीरेश्वर तोमर (बाएं) को विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित किया। (संबंधित खबर : पृष्ठ 10)

दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा धन

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली,
21 फरवरी

- सिसोदिया ने की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने और दिल्ली नगर निगम के लिए मांगा धन

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के लिए धनराशि की मांग की। दिल्ली सरकार को पिछले करीब 20 साल से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर महज 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर कम से कम 7,000 करोड़ रुपये और एमसीडी को 1,250 करोड़ रुपये देने की मांग कर रही है।

सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा, 'केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में मैंने एमसीडी के लिए उसी तरह धन दिए जाने की मांग की जिस प्रकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के निगमों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से देती है। अभी दिल्ली नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मैंने केंद्रीय करों में दिल्ली के लिए भी हिस्सा दिए जाने की मांग की ताकि दिल्ली में स्कूल-अस्पताल खोलने, यमुना को साफ करने, बिजली पानी की व्यवस्था करने आदि के लिए काम और तेजी से किए जा सकें।' सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी देने की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया।

इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र का दौरा किया। इस निगरानी केंद्र में लगी मशीनें एक निश्चित समय में हवा में पीएम-10, पीएम-2.5 और पीएम-1 बढ़ने श घटने का कारण बताने में समक्ष हैं। इस केंद्र से अगले माह आने वाली अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर सरकार जन आंदोलन के जरिये लोगों को जागरूक करेगी और कार्य योजना बनाकर दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने पर प्रभावी कदम उठाएगी।

लाइसेंस हस्तांतरण-विलय नियमों में सुधार के सुझाव

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 21 फरवरी

- यह उपाय दूरसंचार क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहण से संभावित गैर-प्रतिस्पर्द्धा को रोकने में कारगर होंगे
- ट्राई ने सुझाव दिया कि इंटरनेट जैसी सेवाओं की बाजार हिस्सेदारी तय करने में ग्राहकों की संख्या और एजीआर को ध्यान में रखा जाए
- अन्य सेवाओं के लिए एजीआर के आधार पर हो बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी का निर्धारण राजस्व और ग्राहक आधार दोनों के हिसाब से किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी निर्धारण में केवल राजस्व का ध्यान रखा जाएगा। नियामक ने कहा कि दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण और विलय के लिए से सुधार किए गए हैं।

ट्राई इसे सुधारात्मक कदम मान सकता है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में केवल तीन निजी क्षेत्र की कंपनियों के होने से यह सुधार नकाफी है और काफी देर से किया गया है।

एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'ये परिभाषाएं और विभेद उस समय ज्यादा तार्किक होता जब बाजार में काफी सारी कंपनियां थीं लेकिन अब केवल तीन निजी कंपनियों के होने से इसका विशेष लाभ नहीं होगा।' ये उपाय मुख्य रूप से गैर-प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिए हैं जो दूरसंचार क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहण से हो सकते हैं।

ट्राई ने सुझाव दिया है कि इंटरनेट और वीएसएटी सेवाओं के लिए बाजार हिस्सेदारी तय करने में ग्राहकों की संख्या के साथ ही साथ समायोजित सकल राजस्व पर विचार किया जाना चाहिए। बाकी सेवाओं के लिए केवल सकल समायोजित राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा।

प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि इन दिशानिर्देशों को जल्दी से लागू किया जाना चाहिए, जिसका असर स्पेक्ट्रम की बाजार कीमत तय करने पर पड़ेगा। नियामक ने अपने पहले की सिफारिशों को दोहराया जिसमें कहा गया था कि अगर स्पेक्ट्रम हस्तांतरित करने वाली कंपनी उसका एक हिस्सा अपने पास रखती है, जिस पर प्रवेश शुल्क लगता है तो प्राप्तकर्ता इकाई पर बाकी स्पेक्ट्रम के लिए प्रवेश शुल्क के अंतर के भुगतान की देनदारी होगी और यह उस तिथि से लागू होगी जब दूरसंचार विभाग हस्तांतरण या विलय को मंजूरी देगा।

ट्राई ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट की सहमति के बाद विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लाइसेंस के हस्तांतरण व विलय के लिए अभी एक साल की समयसीमा स्वीकार्य है। इस समयसीमा से उस अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए, जो किसी ऐसे मुकदमे में लगे हुए हैं जिनके कारण अंतिम मंजूरी में देरी हुई हो।

दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस के हस्तांतरण एवं विलय की मंजूरियां मिलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के बारे में ट्राई से मई 2019 में सुझाव मांगा था। नियामक ने बाजार हिस्सेदारी की गणना से लेकर मंजूरियों की समयसीमा तथा अन्य शर्तों तक पर सुझाव दिए हैं।

इसके साथ ही नियामक ने यह भी कहा है कि उसके इन दिशानिर्देशों को दूरसंचार क्षेत्र की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि एक दशक पहले जहां इस क्षेत्र में 12 से 14 सेवा प्रदाता मौजूद थे वहीं अब चार सेवा प्रदाता ही इसमें रह गए हैं। नियामक ने कहा कि विलय में देरी और त्वरित मंजूरी को लेकर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की बातों को ध्यान में रखा गया है। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र में तीन निजी कंपनियां - भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड है।

फ्लिपकार्ट ने दी सीसीआई के आदेश को चुनौती

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपने कारोबारी तरीकों की जांच संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले एमेजॉन को उच्च न्यायालय से इसी आदेश पर अंतरिम स्थगन मिल चुका है। सीसीआई ने दिल्ली व्यापार महासंघ से मिली शिकायत पर पिछले महीने फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के कारोबारी तौर-तरीकों की जांच शुरू कर दी थी। दिल्ली व्यापार महासंघ का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन पर भारी छूट दे रहे हैं जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। पृष्ठ 3

कंपनियों को पूंजी संकट, भुगतान में सुस्ती

पवन लाल
मुंबई, 21 फरवरी

भुगतान में देरी

- लॉ फर्मों, एसएमई को भुगतान में तीन से छह महीने की देरी
- वाहन कंपनियां आपूर्तिकर्ताओं से मांग रही हैं बिल में छूट
- बैंक क्रेडिट में सुस्ती और एनबीएफसी संकट से बिगड़े हालात
- कई कंपनियों के बंद होने से बढ़ रहा है भरोसे का संकट

देश की कई बड़ी कंपनियां सेवा प्रदाताओं को भुगतान में देरी कर रही हैं। इससे कंसल्टिंग और लॉ फर्मों तथा छोटी तथा मझोली कंपनियों पर पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। देश की एक प्रमुख कॉरपोरेट लॉ फर्म के संस्थापक पार्टनर ने कहा, 'भुगतान में दो से चार महीने तक की देरी हो रही है। देश की कुछ शीर्ष कंपनियों के बीच ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है।' उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी इस बात का संकेत है कि सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता सूची में वरीयता नहीं दी जा रही है। इसके पीछे यह सोच है कि सेवा प्रदाता कंपनियों के पास विनिर्माण कंपनियों जैसी तात्कालिक मजबूरी नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि लॉ फर्मों की भी वेतन के रूप में भारी इनपुट लागत है। यही नहीं लॉ फर्मों को भी काम रोकना पड़ रहा है और कई मामलों में तो उन्हें अपना बकाया वसूलने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) का सहारा लेना पड़ रहा है।

मझोली आकार की एक लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर ने कहा कि घरेलू कंपनियां ही नहीं बल्कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी दो महीने की देरी से भुगतान कर रही हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। कलपुर्जे बनाने वाली एक कंपनी के एक प्रवर्तक ने कहा कि वाहन बनाने वाली देश की एक बड़ी कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा छूट मांग रही हैं जो एक तरह से कीमतों में कमी का तरीका है।

एक दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि आम धारणा यह है कि चाहे अर्थव्यवस्था में तेजी हो या मंदी, वकील, अकाउंटेंट और सलाहकारों की हमेशा चांदी रहती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में इन पेशों से जुड़ी फर्मों को भुगतान में देरी हो रही है क्योंकि वित्तीय बाजारों में ऋण की स्थिति बेहद तंग है।

ईवाई की वर्किंग कैपिटल एडवाइजरी में पार्टनर और लीडर नवीन तिवारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के आंकड़े कुछ महीने में उपलब्ध होंगे लेकिन सभी संकेतों से साफ है कि नकदी पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा, 'एनबीएफसी में मंदी और सरकारी बैंकों की स्थिति तंग होने से कई कंपनियों की कार्यशील पूंजी तक पहुंच कम हो गई है और इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है।' उन्होंने साथ ही कहा कि नवंबर 2019 में बैंक उधारी में वृद्धि महज 8 फीसदी रही जो नवंबर 2018 में 15 फीसदी थी। कई क्षेत्रों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यशील पूंजी के सिकुड़ने का एक दुष्प्रभाव यह हुआ है कि प्राइवेट इक्विटी फर्में कंपनियों को जरूरी पूंजी मुहैया करा रही हैं। उद्यमियों के पास फंड के बदले इक्विटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

वित्त वर्ष 2020 के लिए क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक विकास की गति उम्मीद से कम रही है, सभी क्षेत्रों में मांग में कमी आई है और कार्यशील पूंजी का चक्र बढ़ गया है जिससे निर्माण सामग्री क्षेत्र जैसे उद्योगों की रेटिंग में कमी आई है।

संक्षेप में

विप्रो डिजिटल की हुई रैशनल इंटरेक्शन

विप्रो डिजिटल ने रैशनल इंटरेक्शन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। हालांकि कंपनी ने इस सौदे की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। कंपनी ने बयान में जानकारी दी कि विप्रो डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो की डिजिटल इकाई है। रैशनल इंटरेक्शन ग्राहकों को डिजिटल अनुभव प्रदान करती है। रैशनल 2009 में बनी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। कंपनी के सिएटल, डबलिन और सिडनी आदि में कार्यालय हैं तथा उसके कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक है। *भाषा*

एलऐंडटी इन्फोटेक निफ्टी नेक्स्ट-50 सूचकांक में

प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो इन्फोटेक (एलटीआई) को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने निफ्टी नेक्स्ट-50 सूचकांक में शामिल किया है। एलटीआई ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। कंपनी जुलाई 2016 में सूचीबद्ध हुई थी। पिछले चार साल में कंपनी ने तेजी से वृद्धि दर्ज की है। निफ्टी नेक्स्ट-50 सूचकांक कंप्यूटर आधारित है, जिसमें कंपनियों के शेयर की कीमत और बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या के बीच गुणा करके मुक्त प्रवाह तरीके से कंपनियों का स्तर तय किया जाता है। एलटीआई ने कहा कि निफ्टी नेक्स्ट-50 में शामिल होना कंपनी के लिए सम्मान की बात है। यह दिखाता है कि कंपनी निवेशकों को आकर्षित करने वाली शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल है। *भाषा*

सन फार्मा ने तोड़े नियम: सेबी

सेबी को सौंपी गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में रकम की हेराफेरी के आरोपों की पुष्टि नहीं

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 21 फरवरी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया है कि प्रमुख औषधि कंपनी सन फार्मास्युटिकल्स ने आदित्य मेडिसेल्स (एएमएल) के साथ संबंधित पक्ष के लेनदेन का खुलासा न करके उसकी सूचीबद्धता एवं खुलासा नियमों का उल्लंघन किया है। एएमएल इस औषधि कंपनी के प्रवर्तकों के स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत में अपने फॉर्मूलेशन का वितरण करती है। हालांकि इस मामले से अवगत दो लोगों ने बताया कि जांच से उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है जिनके तहत 42,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात कही गई थी।

मामले से अवगत उन दो लोगों के अनुसार, बाजार नियामक के जांच विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें सन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ सेबी अधिनियम की धारा 15 के तहत सुनवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सेबी की जांच प्रक्रिया पिछले सप्ताह पूरी हो गई जबकि करीब एक पखवाड़ा पहले बाजार नियामक को एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी गई थी। बाजार नियामक ने सितंबर 2019 में फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था ताकि एक व्हिसलब्लोअर द्वारा कंपनी प्रशासन में चूक और रकम की कथित हेराफेरी के आरोपों की जांच की जा सके।

सन फार्मा के प्रवक्ता ने इस समाचार पत्र द्वारा भेजे गए एक ईमेल के जवाब में कहा, 'कंपनी ने सेबी द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं मुहैया कराई और बाजार नियामक का सहयोग किया।' उन्होंने कहा, 'आपके इस विशेष प्रश्न के संदर्भ में हमें बाजार नियामक से कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए फिलहाल हम उस पर टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हैं।'

उपरोक्त दो व्यक्तियों ने कहा कि सेबी बोर्ड को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस औषधि कंपनी ने एएमएल को संबंधित पक्ष की श्रेणी में नहीं रखा जबकि उसका अंतिम लाभार्थी सन फार्मास्युटिकल्स के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि कंपनी को सूचीबद्धता नियमों के तहत निर्धारित इसका उल्लेख सार्वजनिक तौर पर कना चाहिए था।

एएमएल और सन फार्मा के बीच लेनदेन का खुलासा न होना और उसे एक वितरक के तौर पर वर्गीकृत करना सेबी की सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा जरूरतों का स्पष्ट उल्लंघन है। आमतौर पर कोई तीसरा पक्ष का वितरक विनिर्माता से दवाओं की खरीद करता है और कुछ मार्जिन के साथ ग्राहकों को बिक्री करता है। लेकिन सन फार्मा का एएमएल के साथ जिस तरीके का संबंध है उससे वह उसकी सहायक इकाई है न कि वितरक।

समझा जाता है कि बाजार नियामक इस फारेंसिक रिपोर्ट पर एएमएल के परिचालन को ध्यान में रखते हुए गौर करेगा जिसमें सन फार्मा के साथ उसका अनुबंध भी शामिल है।

सन फार्मा की बढ़ी मुश्किल

- औषधि कंपनी सन फार्मास्युटिकल्स ने आदित्य मेडिसेल्स के साथ संबंधित पक्ष के लेनदेन का खुलासा न करके उसकी सूचीबद्धता एवं खुलासा नियमों का उल्लंघन किया
- फोरेंसिक जांच से उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है जिनके तहत 42,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात कही गई थी

भारत केंद्रित फंडों ने जुटाई रिकॉर्ड पूंजी

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 21 फरवरी

- वर्ष 2019 में इन फंडों ने जुटाए 11.7 अरब डॉलर
- पिछला रिकॉर्ड 2018 में 8.1 अरब डॉलर जुटाने का था

अर्थव्यवस्था में भले ही सुस्ती दिख रही हो लेकिन भारतीय बाजार पर केंद्रित निजी इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडों ने 2019 में 56 दौर के तहत 11.7 अरब डॉलर जुटाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वीसीसीऐज डेटा से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अर्न्सट ऐंड यंग के विश्लेषण के अनुसार, पिछले वर्ष वर्ष के मुकाबले इसमें 45 फीसदी की वृद्धि हुई। पीई/वीसी फंडों द्वारा रकम जुटाने का पिछला रिकॉर्ड 2018 में 8.1 अरब डॉलर का रहा था जिसे 51 दौर के तहत जुटाए गए थे।

कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई घोषणाओं के साथ भारत केंद्रित पीई एवं वीसी फंडों की कुल रकम 30 अरब डॉलर थी जो 2018 में जुटाई गई रकम के मुकाबले कमोबेश बराबर है। साल के दौरान इस प्रकार की सबसे बड़ी पहल भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 1.5 अरब डॉलर की विशेष खिड़की की रही जिसे विशेष तौर पर रियल एस्टेट क्षेत्र की अटकी परियोजनाओं के लिए खोली गई थी। दूसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी एडलवाइस की वैकल्पिक निवेश इकाई रही जिसने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश के लिए 1.29 अरब डॉलर जुटाई।

कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड ने गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए 1 अरब डॉलर जुटाए, चिसकैपिटल ने 85 करोड़ डॉलर जुटाए जबकि इंडिया रीसर्जेंस फंड ने पुनर्गठित ऋण आदि के लिए 75 करोड़ डॉलर जुटाए।

एक अग्रणी पीई फर्म के शीर्ष अधिकारियों ने कहा, 'इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। चार से पांच वर्ष पुराने भारत केंद्रित फंडों में वैश्विक निवेशकों को रिटर्न का दायरा 2.5 से 3 फीसदी रहा है। निवेश समेटने में थोड़ी स्थिरता दिखने के साथ वे भारत केंद्रित फंडों में और निवेश करना चाहते हैं।'

प्रमुख वैश्विक पीई कंपनियों का कहना है कि इसमें वैश्विक पीई फंडों द्वारा जुटाए गए एशियाई फंडों को शामिल नहीं किया गया है जिनका भारत में निवेश 20 से 30 फीसदी के दायरे में है।

सिंटेक्स प्रीफैब के खिलाफ दिवाला याचिका एनसीएलएटी ने सिंटेक्स प्रीफैब ऐंड इन्फ्रा के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने की लॉयड इंसुलेशंस की याचिका खारिज कर दी। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की पीठ ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद हैं। *भाषा*

अब बैंकों की नजर छोटे दिवालिया मामलों पर

ईशिता आयान दत्त और नम्रता आचार्य
कोलकाता, 21 फरवरी

एस्सार स्टील और भूषण स्टील जैसे बड़े दिवालिया मामलों के निपटने के बाद अब बैंकरों की नजर वसूली दर को कम से कम 20 से 30 फीसदी पर बरकरार रखने पर है। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2019 तक 190 समाधान योजनाओं के तहत वित्तीय लेनदारों की प्राप्तियां 1.52 लाख करोड़ रुपये यानी 43.14 फीसदी रहीं। जबकि दावों की रकम 3.61 लाख करोड़ रुपये थी।

दिलचस्प है कि कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों में से 1 लाख करोड़ रुपये की वसूली महज चार इस्पात कंपनियों से हुई। इन कंपनियों में एस्सार स्टील, भूषण स्टील, भूषण पावर ऐंड स्टील और इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स शामिल हैं। हालांकि अब बैंक अब ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत अधिक वसूली की उम्मीद नहीं कर रहे हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दूसरी सूची के तहत 28 कंपनियों को समाधान के लिए भेजा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरबीआई की दूसरी सूची के तहत करीब 30 फीसदी वसूली होने की उम्मीद है। एक अन्य शीर्ष बैंकर ने कहा कि एक मामले में 50 करीब 50 फीसदी वसूली होने की उम्मीद है और यदि इसे छोड़ दिया जाए तो दूसरी सूची में शामिल कंपनियों से 25 से 30 फीसदी की वसूली हो सकती है।

एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, 'सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है लेकिन इसे लागू करने का जज्बा अच्छा नहीं दिखा है। कुछ मामलों में समाधान की रकम 30 फीसदी से भी कम है जबकि कभी-कभी यह रकम 15 फीसदी से भी कम रही है। परिसमापन मूल्य काफी कम रहा है।' हालांकि उन्होंने कहा कि बैंक अब भी निपटान के लिए आईबीसी को प्राथमिकता दे सकते हैं क्योंकि यह एक पारदर्शी तरीका है।

सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी मृत्युंजय महापात्र के अनुसार, आईबीसी से ऋण संस्कृति में सुधार लाने में मदद मिली है और कुल मिलाकर समाधान की रकम में वृद्धि हुई है क्योंकि पुराने मामलों में परिसंपत्तियों के पुराने होने से मूल्य काफी घट चुका था। उन्होंने कहा, 'आईबीसी के तहत उपचारात्मक और सुधारात्मक दोनों मूल्य है। इससे पहले प्रवर्तक विभिन्न तरीकों को आजमाते थे और उनकी सूचनाओं में कोई तालमेल नहीं होता था। विभिन्न लेनदारों को एक ही समय में अलग-अलग जानकारी दी जाती थी। लेकिन आईबीसी के तहत समधान को समयबद्ध बनाया गया है। आगे चलकर समधान मूल्य में भी सुधार होगा।' महापात्र ने कहा, 'साथ ही आईबीसी को केवल वसूली के आधार पर ही नहीं आंकना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भी समान रकम प्राप्त हो सकती है।' इक्रा के उपाध्यक्ष अभिषेक डफरिया ने कहा कि समाधान प्रक्रिया के जरिये वसूली गई रकम खास मामले पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, 'आईबीसी के तहत लाए गए कुछ मामले करीब एक दशक पुराने हैं और इसलिए परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। कोई यह उम्मीद कर सकता है कि आगे चलकर लेनदारों द्वारा मामले शुरुआती चरण में लाए जाएंगे जिससे वसूली बेहतर होने की संभावना होगी।'

डफरिया ने यह भी कहा कि वसूली की रकम कंपनी और उससे संबंधित उद्योग पर भी निर्भर करेगी कि वहां तेजी का रुख है अथवा मंदी का। उदाहरण के लिए, इस्पात कंपनियों से वसूली काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी, सुरक्षा और डंपिंगरोधी शुल्क आदि से संचालित थी।

निपटाए गए मामले (दिसंबर 2019 तक)

190 मामले निपटाए गए

3.52 लाख करोड़ रुपये दावे की कुल रकम

1.52 लाख करोड़ रुपये एफसी द्वारा वसूली योग्य*

चार बड़े मामले

■ वसूली की रकम (करोड़ रुपये)

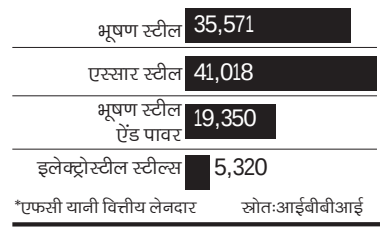

*एफसी यानी वित्तीय लेनदार स्रोत:आईबीबीआई

जीएमआर-ग्रुप एडीपी सौदे को सीसीआई की मंजूरी

एजेंसियां
नई दिल्ली, 21 फरवरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एयरपोर्ट कारोबार की 49 फीसदी हिस्सेदारी फ्रांस की ग्रुपे एडीपी को बेचने के जीएमआर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियामक की मंजूरी ग्रीन चैनल से मिलने के बावजूद इसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने गुरुवार को कहा था कि फ्रांसीसी समूह उसके एयरपोर्ट व्यवसाय में 49 फीसदी हिस्सेदारी लेने जा रहा है। इस पर 10,780 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। जीएमआर इस सौदे में मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने कर्ज बोझ को कम करने के लिए करेगा।

प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने शुक्रवार को प्रसारित एक ट्वीट में बताया कि उसे फ्रांस की कंपनी एयरपोर्ट डी पेरिस एसए (एडीपी) से ग्रीन चैनल से एक आवेदन मिला है जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 49 फीसदी हिस्सेदारी और जीएमआर इन्फ्रा सर्विसेज लिमिटेड की 100 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण का उल्लेख है। ग्रीन चैनल से प्राप्त आवेदनों को खुदबखुद मंजूर मान लिया जाता है।

एडीपी ने सीसीआई को सौंपी नोटिस में बताया है कि वह हवाईअड्डों का परिचालन करने के साथ ही होल्डिंग कंपनी जीएमआर इन्फ्रा सर्विसेज में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी और फिर जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड में भी 49 फीसदी हिस्सेदारी लेगी। जीएमआर इन्फ्रा सर्विसेज का बुनियादी काम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड में शेयरधारिता बनाए रखना है।

शेयर खरीद समझौते के मुताबिक ग्रुपे एडीपी 10,780 करोड़ रुपये में एयरपोर्ट्स लिमिटेड में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इस राशि में से 9,780 करोड़ रुपये जीएमआर समूह द्वारा शेयरों की द्वितीयक बिक्री के एवज में लगाए जाएंगे जबकि 1000 करोड़ रुपये की रकम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड में इक्विटी डालने के लिए लगेगी।

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा था कि उसका एयरपोर्ट कारोबार पर प्रबंधकीय नियंत्रण बना रहेगा जबकि एडीपी के पास जीएएल एवं अनुषंगी इकाइयों पर परंपरा-मुताबिक अधिकार और बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। पहले यह चर्चा थी कि जीएमआर समूह एयरपोर्ट कारोबार में टाटा समूह के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन जीएमआर के प्रवक्ता ने टाटा के साथ किसी भी सौदे को नकार दिया।

अब फ्लिपकार्ट ने दी प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को चुनौती

कारोबारी तौर-तरीकों की जांच के आदेश पर एमेजॉन को मिल चुकी है राहत

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 21 फरवरी

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपनी कारोबारी तरीकों की जांच संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी है। इसके पहले एमेजॉन को उच्च न्यायालय से इसी आदेश पर अंतरिम स्थगन मिल चुका है।

सीसीआई ने कारोबारियों की संस्था दिल्ली व्यापार महासंघ से मिली शिकायत के बाद पिछले महीने फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के कारोबारी तौर-तरीकों की जांच शुरू कर दी थी। कारोबारी संगठन ने कहा है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन पर भारी छूट दे रहे हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। इस शिकायत की जांच का आदेश जारी होने के बाद एमेजॉन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिछले हफ्ते रिट याचिका दायर की थी। लगातार तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने सीसीआई की जांच पर फौरी रोक लगा दी है। इस मामले में एमेजॉन ने सीसीआई, व्यापार महासंघ और फ्लिपकार्ट को पक्ष बनाया है।

आदेश को चुनौती

- व्यापारियों के संगठन ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन पर भारी छूट दे रहे हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है
- इस शिकायत की जांच का आदेश जारी होने के बाद एमेजॉन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिछले हफ्ते रिट याचिका दायर की थी
- सुनवाई के बाद न्यायालय ने सीसीआई की जांच पर फौरी रोक लगा दी है

एमेजॉन को मिली राहत के बाद फ्लिपकार्ट ने भी उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट को उम्मीद है कि एमेजॉन की तर्ज पर उसे भी अदालत से फौरी राहत मिल जाएगी और स्थगन आदेश जारी हो जाएगा।

इस सूत्र ने कहा, 'फ्लिपकार्ट भी प्रतिस्पर्द्धा आयोग के उसी आदेश को चुनौती दे रही है जिसका विरोध एमेजॉन ने किया था। भले ही इस जांच आदेश पर रोक लग गई है लेकिन तकनीकी तौर पर इसे फ्लिपकार्ट ने अभी तक चुनौती नहीं दी थी। हमारा मानना है कि यह सुनवाई बेहद संक्षिप्त रहेगी क्योंकि अदालत ने इस मामले में पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। जल्द ही इसकी सुनवाई होगी।'

कानूनी जानकारों के मुताबिक फ्लिपकार्ट को इस वजह से याचिका लगानी पड़ी है कि वह एमेजॉन की रिट याचिका में पक्षकार भी बनाई गई थी। फ्लिपकार्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीसीआई जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। हम सीसीआई के इस आदेश का एक पक्ष हैं और इसके खिलाफ दायर एमेजॉन की रिट याचिका में एक प्रतिवादी हैं। हालात और न्यायालय के स्थगन आदेश को देखते हुए एक प्रक्रियागत मामले के तौर पर हम भी एक रिट दायर कर रहे हैं।'

सूत्रों के मुताबिक, प्रतिस्पर्द्धा आयोग के आदेश के खिलाफ फ्लिपकार्ट की मुख्य आपत्ति प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 19(3) को लेकर है। इस धारा में छह मानदंडों का उल्लेख है जिनके आधार पर आयोग यह आकलन कर सकता है कि किसी कंपनी ने निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है। इन मानदंडों में नई कंपनियों की राह में अड़चन खड़ी करना, मौजूदा प्रतियोगियों को बाजार से बाहर करना और उत्पादन या वस्तओं के वितरण या सेवाओं में सुधार शामिल हैं। फ्लिपकार्ट की याचिका में इस बात का जिक्र है कि जांच का आदेश जारी करते वक्त सीसीआई ने इनमें से कुछ मानकों पर सीसीआई ने गौर नहीं किया।

वैश्विक स्तर पर मुद्रा में सुस्ती के बीच टिका रहा रुपया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 21 फरवरी

भारतीय रुपया ऐसे समय में मोटे तौर पर स्थिर बना हुआ है जब वैश्विक मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट का सामना कर रही हैं। इस साल अब तक ब्राजील का रियाल 8.31 फीसदी टूटा है, वहीं उभरते बाजारों की अन्य मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले 3.5-7.5 फीसदी की गिरावट आई है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त की चिंताओं के कारण है।

डॉलर इंडेक्स बढ़कर 99.4850 पर पहुंच गया, जो जनवरी में 97.5 के स्तर पर था। इस साल अब तक यूरो 3.55 फीसदी टूटा है जबकि जापानी येन में डॉलर के मुकाबले 2.80 फीसदी की गिरावट आई है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से उबर रही है, लेकिन कोरोनावायरस के संकट ने चीन से इनपुट पर असर डाला है, जो वैश्विक बढ़त की रफ्तार को नीचे की ओर खींच सकती हैं। यह कहना है विभिन्न एजेंसियों का। इससे अमेरिकी डॉलर जैसी सुरक्षित मुद्रा की मांग बढ़ी हो सकती है।

हालांकि भारत की बढ़त की रफ्तार हालांकि घटी है, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निवेश कर रहे हैं। यहां तक कि बजट के समय उन्होंने अपने डेट में निवेश घटाया था, लेकिन अब विदेशी निवेशक डेट में दोबारा निवेश शुरू कर चुके हैं।

वास्तव में करेंसी डीलरों ने कहा कि सेंट्रल बैंक हस्तक्षेप कर रहा है ताकि मुद्रा में और मजबूती न हो। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 71.66 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपये ने साल 2019 की समाप्ति 71.38 के साथ की थी।

ब्राजील का रियाल 8.31 फीसदी टूटा है, वहीं उभरते बाजारों की अन्य मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले 3.5-7.5 फीसदी की गिरावट आई है

इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने स्थानीय इक्विटी व डेट में 3.429 अरब डॉलर निवेश किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बजट के बाद निवेश हुआ है। आम बजट के बाद से शुद्ध निवेश करीब 3 अरब डॉलर रहा है क्योंकि निवेशकों ने बॉन्ड की खरीद में इजाफा किया है। वे बजट से पहले डेट में शुद्ध बिकवाल रहे थे।

एक बैंक के ट्रेजरी प्रमुख के मुताबिक, हाल के समय में बॉन्ड का प्रतिफल हालांकि घटा है, लेकिन यह अभी भी विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षक स्तर मुहैया करा रहा है। चूंकि मुद्रा में उतारचढ़ाव नियंत्रण मे है, लेकिन विदेशी निवेशक को बिना हेजिंग के आधार पर 3-4 फीसदी लाभ होगा, यह मानते हुए कि रुपये में स्वाभाविक तौर पर 2 फीसदी ह्रास होगा।

सरकारी प्रतिभूतियों को वैश्विक सूचकांकों में शामिल कराने के प्रयास

भाषा
नई दिल्ली, 21 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डों को वैश्विक सूचकांकों में जल्द से जल्द शामिल करने के प्रयास जारी हैं और केंद्रीय बैंक ने कुछ संस्थानों के साथ इस बारे में पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। सरकारी प्रतिभूतियों के वैश्विक सूचकांक में शामिल होने से देश में विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ेगा क्योंकि कई विदेशी कोष वैश्विक सूचकांक पर नजर रखते हैं।

विदेशी कोषों के देश में आने से घरेलू पूंजी उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी और उनकी नकदी की तंगी की शिकायत को दूर करने में मदद मिलेगी।

शक्तिकांत दास ने कहा, इस पर काम चल रहा है। कुछ संस्थानों के साथ हमारी बातचीत हुई है, जो कि इन वैश्विक सूचकांकों को देखते हैं। इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बता सकता हूं लेकिन इस पर काम जारी है। हमारा प्रयास है कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ाया जाए। विदेशी निवेशकों की तरफ से लंबे समय से यह सुझाव दिया जा रहा था, जिसे इस साल के बजट में शामिल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020- 21 के बजट में कहा है, सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ खास श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रवासी भारतीय निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खोला जाएगा। दुनियाभर में कुछ बड़े संस्थागत निवेशक हैं जो लगातार इन सूचकांकों पर नजर रखते हैं। ब्लूमबर्ग बारक्लेज इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स जैसे कुछ सूचकांक हैं, जिनका इस्तेमाल सॉवरिन बॉन्ड में निवेश के फैसलों में किया जाता है।

गैर- बैंकिंग क्षेत्र की सेहत के बारे में पूछे जाने पर गवर्नर दास ने कहा कि रिजर्व बैंक शीर्ष 50 एनबीएफसी पर निगाहें रखे हुए हैं। वास्तव में हम ऐसी निगाहें रखे हुए हैं कि बाहर से कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जुटाएगा 2,000 करोड़ रु.

अभिजित लेले
मुंबई, 21 फरवरी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बॉन्ड के जरिए 2,000 करोड़ रुपये की टियर-2 ऋण पूंजी जुटाने जा रहा है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में मजबूती और कारोबारी बढ़त को सहारा देने के लिए बैंक रकम जुटा रहा है। निजी क्षेत्र के बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2019 के आखिर में 13.29 फीसदी था। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875 फीसदी होना चाहिए जबकि सीईटी-1 अनुपात 8.875 फीसदी। नियामकीय अनिवार्यता के मुकाबले बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत है।

इसके अलावा बैंक के पास एटी-1/टियर-2 बॉन्ड के जरिए रकम जुटाने की पर्याप्त गुंजाइश है ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18 फीसदी के पार जा सके। बैंक ने बीएसई को दी सूचना में ये बातें कही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बैंक के टियर-1 बॉन्ड को एए/स्थिर रेटिंग दी है।

बैंक की रणनीति लोनबुक में इजाफा न करते हुए पूंजी बचाने की रही है और खुदरा लोनबुक का अनुपात बढ़ाकर मार्जिन में इजाफा करने की है। वह भविष्य के लिए

भी पूंजी बचाना जारी रखेगा।

बैंक की वित्त पोषित परिसंपत्ति दिसंबर 2019 में मामूली बढ़कर 1,06,140 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 1,04,660 करोड़ रुपये रही।

आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के विलय के बाद 18 दिसंबर 2018 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अस्तित्व में आया।

विलय के बाद की शुरुआती कुछ तिमाहियों में आईडीएफसी फर्स्ट ने सक्रियता के साथ दबाव वाली परिसंपत्तियों की पहचान की और उसके लिए प्रावधान किया। साथ ही मजबूत खुदरा फ्रैंचाइजी बनाने के लिए अपनी पहुंच में विस्तार पर निवेश किया।

क्रिसिल ने कहा कि पूंजीकरण बेहतर है जैसा कि दिसंबर 2019 में कुल 13.29 फीसदी सीएआर के तौर पर प्रतिबिंबित हुआ जबकि 31 मार्च को यह 15.47 फीसदी था।

कोरोनावायरस के डर के बीच भारतीय आईटी व दूरसंचार शेयर सुरक्षित दांव

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 21 फरवरी

वैश्विक इक्विटी बाजार में अल्पावधि में उतारचढ़ाव बना रह सकता है क्योंकि कोरोनावायरस का डर बना हुआ है, लेकिन इस अवधि का इस्तेमाल निचले स्तर पर शेयरों की खरीद में किया जा सकता है। यह कहना है अग्रणी बाजार विशेषज्ञों का। उनका कहना है कि बाजार उम्मीद कर रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में मजबूत हो जाएगा, जो वैश्विक स्तर पर मुख्य सूचकांकों को आगे ले जाएगा।

जेफरीज के वैश्विक प्रमुख (इक्विटी रणनीति) क्रिस्टोफर वुड ने साप्ताहिक नोट ग्रिड ऐंड फियर में निवेशकों से कहा है, कोरोनावायरस अभी भी है लेकिन चीन में संक्रमण की दर घट रही है और ज्यादातर मामले दुर्भाग्यशाली हुबेई प्रांत तक सीमित रहे हैं। अभी भी इसे लेकर जोखिम है, लेकिन खास तौर से शेयर बाजार दूसरी तिमाही में चीन में मजबूत सुधार की उम्मीद कर रहा है।

जेफरीज के चीन के रणनीतिकार अलेक्सियस ली को उम्मीद है कि 30 करोड़ प्रवासी कामगारों में से 20-30 फीसदी मार्च की शुरुआत से पहले काम पर लौट आएंगे और मार्च 2020 के आखिर तक 40-50 फीसदी और कामगार काम पर लौटेंगे।

एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में कारोबार व पर्यटन में गिरावट थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और कोरिया को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसमें इंडोनेशिया और भारत पर सबसे कम असर पड़ेगा और बीएनपी पारिबा के विश्लेषकों ने हालिया रिपोर्ट में ये बातें कही है। बीएनपी पारिबा

के इक्विटी रिसर्च प्रमुख (एशिया प्रशांत) मनीषी रायचौधरी ने लिखा है, कोरिया, जापान, थाइलैंड, हॉन्ग-कॉन्ग और ताइवान पर आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। उभरते बाजारों में कमजोर धारणा से भारत व इंडोनेशिया के चालू खाते के घाटे पर असर पड़ सकता है।

ऐसे में बीएनपी पारिबा ने चीन के लिए 2020 की जीडीपी की की रफ्तार 1.2 फीसदी घटाकर 4.5 फीसदी कर दी है। 2020 के लिए उनकी जीडीपी की रफ्तार का अनुमान 3.0 फीसदी से घटाकर 2.6 फीसदी कर दिया गया है।

कहां करें निवेश?

कोरोनावायरस का डर बने रहने तक अल्पावधि में उतारचढ़ाव बना रह सकता है। इस डर में कमी आने के बाद बीएनपी पारिबा का मानना है कि भारतीय बाजार कोरोनावायरस के प्रसार से अपेक्षाकृत बचा रहेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार कंपनियां इस स्थिति में सुरक्षित निवेश का ठिकाना बना हुआ है।

वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती तेल कंपनी है ओएनजीसी

सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी अब वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती तेल व गैस कंपनी है। इस हफ्ते कंपनी का शेयर 15 साल में पहली बार 100 रुपये के नीचे चला गया। अभी ओएनजीसी एक साल आगे की अनुमानित आय के 4.2 गुने पर कारोबार कर रही है। वैश्विक स्तर पर ज्यादातर तेल व गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां 15 गुने से ज्यादा पीई पर कारोबार कर रही हैं। एक्सॉन मोबिल और सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी (सऊदी अरामको) का पीई क्रमश: 18.3 गुना व 17.3 गुना है। ओएनजीसी हमेशा से ही वैश्विक स्तर पर समकक्ष कंपनियों के मुकाबबले छूट पर कारोबार करती रही है, लेकिन हाल के महीनों में यह छूट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों पिनाकिन पारेख और संकेत परब ने एक नोट में कहा है, ओएनजीसी की ट्रेडिंग 4.2 गुने पीई पर हो रही है और वैश्विक कंपनियों के बीच यह सबसे सस्ता शेयर है। स्वीकार्य रूप से ओएनजीसी ने वैश्विक कंपनियों के मुकाबले ऐतिहासिक तौर पर छूट पर कारोबार किया है, लेकिन पिछले 12 महीने में यह छूट काफी ज्यादा बढ़ गया है।

ब्रोकरेज ने इसे खरीद की सलाह दी है, हालांकि लक्षित कीमत 190 रुपये से घटाकर 172 रुपये कर दी गई है क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमजोरी के बीच आय अनुमान में कटौती हुई है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि यह शेयर करीब 8 फीसदी के आकर्षक प्रतिफल की पेशकश करता है। उसने ओएनजीसी की बेहतरी के लिए कुछ अन्य संकेतकों की पहचान की है। नोट में कहा गया है, हमारी राय में निकट भविष्य में इस शेयर के आगे बढ़ने के दो संभावित उत्प्रेरक हैं - पहला, उत्पादन के प्रोफाइल में सुधार, जो अभी दो तिमाही दूर है। दूसरा, बीपीसीएल का कामयाब निजीकरण, जो नकदी संपन्न ओएनजीसी जैसी पीएसयू के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं (एचपीसीएल की हिस्सेदारी खरीद के समान) देने के मामले में जोखिम घटाता है।

समी मोडक

दुनिया की सबसे मूल्यवान तेल कंपनियों की तुलना में ओएनजीसी

कंपनी	पी/ई (गुणक)	मार्केट कैप	बिक्री	लाभ
एक्सॉन मोबिल कॉर्प	18.3	253	244	14.3
सऊदी अरामको	17.3	1,794	315	110.9
शेवरॉन कॉर्प	16.2	208	140	2.9
पेट्रोलियो ब्रासीलीरो	11.5	92	77	10.2
बीपी पीएलसी	11.4	120	278	4.0
पीटीटी थाईलैंड	11.3	40	72	3.0
एनी इटली	11.0	50	90	4.9
पेट्रो चाइना	10.6	133	356	8.0
इक्विनोर नॉर्वे	10.2	57	63	1.8
ओएनजीसी	4.2	18	65	4.4

स्रोत : ब्लूमबर्ग, आंकड़े अरब डॉलर में नोट : बिक्री और लाभ पूरे साल के लिए।

सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों में गिरावट से निवेशक परेशान

कृष्ण कांत और देव चटर्जी
मुंबई, 21 फरवरी

हाल तक भारत की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) में से एक ओएनजीसी का शेयर 15 साल के निचले स्तर पर आने के बाद अब नजरें केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली फर्मों पर है, जो भारतीय एक्सचेंजों पर सबसे ज्यादा पिछड़ने वाली कंपनी बन गई है।

62 पीएसयू का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 15.4 लाख करोड़ रुपये है, जो चार साल के निचले स्तर के करीब है और भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ दें तो यह मार्च 2009 के बाद के न्यूनतम स्तर पर आ गया है।

पीएसयू का बाजार पूंजीकरण मौजूदा वित्त वर्ष में 17.6 फीसदी नीचे है जबकि बेंचमार्क एनएसई निफ्टी-50 इंडेक्स इस अवधि में 4.3 फीसदी चढ़ा है। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ दें (बाजार पूंजीकरण के लिहाज से सबसे बड़ी पीएसयू) तो पीएसयू इंडेक्स पिछले साल मार्च के आखिर के बाद 21.4 फीसदी टूटा है और पिछले तीन साल में इसमें 28 फीसदी की गिरावट आई है, जो उसे सबसे ज्यादा परिसंपत्ति गंवाने वालों में शामिल करता है। एसबीआई का

- 62 पीएसयू का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 15.4 लाख करोड़ रुपये है, जो चार साल के निचले स्तर के करीब है
- पीएसयू का बाजार पूंजीकरण मौजूदा वित्त वर्ष में 17.6 फीसदी नीचे है जबकि निफ्टी-50 इंडेक्स इस अवधि में 4.3 फीसदी चढ़ा है
- पिछले पांच साल में पीएसयू का संयुक्त राजस्व सालाना 4.8 फीसदी चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ा है

प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और पिछले तीन साल में उसके बाजार पूंजीकरण में सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से 18.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले तीन साल में पीएसयू का बाजार पूंजीकरण 7.1 फीसदी घटा है और यह मार्च 2017 के आखिर के 19.2 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 18 फरवरी को 15.4 लाख करोड़ रुपये रह गया। इस अवधि में एनएसई-50 इंडेक्स में सालाना 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। ओएनजीसी का शेयर जनवरी 2018 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के अधिग्रहण के बाद शुरू हुई।

विश्लेषकों ने कहा कि ओएनजीसी के शेयर में गिरावट की मुख्य वजह दिसंबर तिमाही में कंपनी का कमजोर प्रदर्शन रही। एक विदेशी ब्रोकरेज के विश्लेषक ने कहा, 37,000 करोड़ रुपये की नकदी में एचपीसीएल का अधिग्रहण निवेशकों को रास नहीं आया। इसी वजह से ओएनजीसी के शेयर में गिरावट का रुख है।

कंपनी के कमजोर प्रदर्शन की वजह सुसस्त आय और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के इर्द-गिर्द बनी नकारात्मक धारणा रही है। इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी सर्विसेज के संस्थापक व प्रबंध निदेशक जी. चोकालिंगम ने कहा, पिछले कुछ साल में पीएसयू की आय की रफ्तार काफी उत्साहजनक नहीं रही है, लेकिन निवेशक उन कंपनियों से भी दूर हट रहे हैं जिनकी आय की रफ्तार अच्छी है क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के इर्द-गिर्द नकारात्मक धारणा बनी हुई है।

पिछले पांच साल में पीएसयू (बैंक व गैर-बैंक समेत) का संयुक्त राजस्व सालाना 4.8 फीसदी चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ा है और यह 2013-14 के 23.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 29.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस अवधि में संयुक्त रूप से उनका शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2014 के 1.5 लाख करोड़ रुपये से घटकर पिछले साल मार्च के आखिर में 60,300 करोड़ रुपये रह गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच साल में लाभ में सबसे बड़ी गिरावट देखी है। सूचीबद्ध एनबीएफसी समेत पीएसयू के लेनदारों का संयुक्त रूप से शुद्ध नुकसान वित्त वर्ष 2019 में 57,000 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2014 में उनका शुद्ध लाभ 65,500 करोड़ रुपये रहा था।

कुल मिलाकर इन लेनदारों ने पिछले पांच साल में 1.34 लाख करोड़ रुपये गंवाए हैं। पीएसयू का संयुक्त नकदी भंडार पिछले साल मार्च के आखिर में 15 साल के निचले स्तर 85,000 करोड़ रुपये पर आ गया, जो मार्च 2014 के आखिर में 1.74 लाख करोड़ रुपये था।

कई पीएसयू पूंजीगत खर्च के लिए और अन्य पीएसयू के अधिग्रहण या विशेष लाभांश के लिए उधार लेने को बाध्य हुई हैं, जिससे उनकी बैलेंस शीट में गिरावट आई है। गैर-वित्तीय पीएसयू का शुद्ध कर्ज-इक्विटी अनुपात पिछले साल मार्च के आखिर में 0.71 गुने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, जो एक साल पहले 0.62 गुना था और मार्च 2014 के आखिर में 0.44 गुना। पीएसयू का शुद्ध कर्ज पिछले पांच साल में दोगुने से ज्यादा हो गया है। उनका कर्ज पिछले साल मार्च के आखिर में 6.02 लाख करोड़ रुपये था, जो एक साल पहले 4.98 लाख करोड़ रुपये और मार्च 2014 के आखिर में 2.96 लाख करोड़ रुपये था।

मुथूट फाइनैंस : हर चमकीली चीज है सोना

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 21 फरवरी

पिछले साल शेयर कीमतों में 75 फीसदी से ज्यादा की तेजी ने मुथूट फाइनैंस को अग्रणी रेटिंग वाली वित्तीय सेवा कंपनियों मसलन बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक की श्रेणी में ला दिया है और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एचडीएफसी एएमसी के पास।

मजे की बात यह है कि एक्सचेंजों पर इस कंपनी ने एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे नामों को विस्थापित कर दिया है।

सोने की कीमतों में तेजी के कारण मजबूत बढ़ोतरी जैसे कारकों से उचित दर पर पूंजी जुटाने की फर्म की क्षमता व विशाखित करने की कोशिश ने इस बढ़ोतरी में योगदान किया है।

उदाहरण के लिए दिसंबर तिमाही में गोल्ड लोनबुक में सालाना आधार पर 19 फीसदी की बढ़ोतरी ने पिछली तिमाही में 9 फीसदी की गिरावट की भरपाई कर ली है, ऐसे में एक हफ्ते में शेयर 23 फीसदी चढ़ गया।

तीसरी तिमाही में मुथूट के पास सोना सालाना आधार पर 4.2 फीसदी बढ़कर 173 टन पर पहुंच गया। इस साल अब तक प्रबंधनाधीन स्वर्ण परिसंपत्तियां 12 फीसदी बढ़ी हैं जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 10 फीसदी बढ़ा था, जो संकेत देता है कि वित्त वर्ष 2020 की समाप्ति अनुमान के मुकाबले ज्यादा मजबूती के साथ होगी।

इसके अतिरिक्त गोल्ड लोन कारोबार में इसकी वर्चस्व की स्थिति उसे अपनी समकक्ष कंपनियों पर बढ़त प्रदान करता है।

कंपनी की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां तीसरी तिमाही में घटकर 2.54 फीसदी रह गई, जो दूसरी तिमाही में 3.43 फीसदी थी। आईडीबीआई कैपिटल के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा है कि गोल्ड लोन कारोबार में एनपीए वास्तव में परेशानी का कारण नहीं है।

मुथूट फाइनैंस ने वरिष्ठ सुरक्षित नोट जारी कर 55 करोड़ डॉलर जुटाने के मामले में कीमत तय करने की घोषणा की है, जो 4.4 फीसदी की दर पर होगा और साढ़े तीन साल के लिए होगा। कंनपी की तरफ से यह दूसरा बॉन्ड इश्यू है।

संक्षेप में

70 प्रतिशत मालवहन के जाम मुक्त होने की उम्मीद

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) को देश में मालवाहक रेलगाड़ियों की गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करने के साथ ही भारतीय रेलवे के 70 प्रतिशत मालवहन बोझ के खत्म होने की उम्मीद है। डीएफसीसीआईएल का मानना है कि इससे यात्री गाड़ियों के परिचालन की क्षमता बेहतर होगी। डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक अनुराग सचान ने संवाददाताओं से कहा कि हमारा गलियारा पूरी तरह मालवहन को समर्पित है। *भाषा*

उद्योग संगठनों को हल्के में नहीं ले कारोबार जगत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को उद्योग जगत को हिदायत दी कि उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कोई समस्या खड़ी होने पर ही कारोबारी इन संगठनों का रुख करते हैं। उन्होंने एआईएमए के एक कार्यक्रम में कहा- मैंने सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के कार्यक्रमों में कई बार ऐसा पाया है कि उनमें महज मौजूदा अध्यक्ष, कुछ पूर्व पदाधिकारी, भावी अध्यक्षगण और कुछ संभवत: जागरूक पदाधिकारी ही मौजूद होते हैं। *भाषा*

भारत आने को तैयार ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 21 फरवरी

सरकार की ओर से ई-कॉमर्स नीति को लेकर किए जा रहे बदलाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की परेशानियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की खाद्य, स्वास्थ्य और सौंदर्य क्षेत्रों की खुदरा कंपनियां ऑनलाइन के माध्यम से भारत के बाजार में प्रवेश को तैयार हैं।

स्थानीय भंडारण अनिवार्य किए जाने के हाल के भारत के डेटा कानून के शोध के साथ तमाम कंपनियं भात में बैकग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की भी प्रक्रिया में हैं, जिससे ऑनलाइन खुदरा को समर्थन मिल सके।

ऑस्ट्रेलियन ट्रेड ऐंड इन्वेस्टमेंट कमीशन (ऑस्ट्रेड) के ट्रेड कमिश्नर-साउथ एशिया मार्क मोर्ले ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस एक्सचेंज (एआईबी-एक्स) के हिस्से के रूप में अगले सप्ताह 150 सदस्यों का मजबूत प्रतिनिधिमंडल भारत जाएगा, जिसमें तमाम कंपनियों की निवेश की योजना भी है। वाणिज्य मंत्री सिमोन बर्मिंघम भी इस दौरान मौजूद होंगे।'

मोरले ने कहा कि भारत के प्रतिबंधों से निपटने के बाद ऑस्ट्रेलिया से बेहतर गुणवत्ता का जौ भी अब भारत भेजे जाने को तैयार है। इसके साथ ही वाइन उत्पादक भी भारत में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।

एआईबी-एक्स ऑस्ट्रेलिया सरकार का भारत में कारोबार सृजन को लेकर कई महीने का कार्यक्रम है। इसमें मंत्री स्तर का द्विपक्षीय दौरा और प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों शिक्षा, कृषि कारोबार, रिसोर्सेज और पर्यटन के कई ट्रेड शो शामिल किए गए हैं। साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र को भी महत्त्व दिया जा रहा है।

ज्यादा मूल्य वाले क्षेत्रों जैसे पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार के मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कारोबार अन्य समान विकसित देशों की तुलना में कम है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां बड़ा कारोबारी साझेदार है, जिसके साथ 2018-19 में वस्तु एवं सेवाओं का 30.3 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला 25वां बड़ा स्रोत है। भारत के कारोबारी घाटा का मुख्य वजह 2019-20 के पहले 8 महीने में कोयला और प्राकृतिक गैस के 5.6 अरब डॉलर के निर्यात की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया से कुल आयात इस अवधि के दौरान बढ़कर 7.8 अरब डॉलर हो गया, जो भारत से हुए 2.2 अरब डॉलर निर्यात की तुलना में 3 गुने से ज्यादा है।

अगले सप्ताह आ रहा है 150 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

- ऑस्ट्रेलिया की खाद्य, स्वास्थ्य और सौंदर्य क्षेत्रों की खुदरा कंपनियां ऑनलाइन कारोबार के माध्यम से भारत के बाजार में प्रवेश को तैयार
- अगले सप्ताह आ रहे 150 सदस्यों के आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां के वाणिज्य मंत्री सिमोन बर्मिंघम भी
- प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों शिक्षा, कृषि कारोबार, रिसोर्सेज और पर्यटन के कई ट्रेड शो और मंत्रिस्तरीय वार्ता होगी
- केपीएमसी के साथ सीईए की नई रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा जरूरत की वृद्धि दर 2021-22 से 2026-27 तक 5.22 फीसदी

भारत पर ध्यान

वहीं दूसरी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया का आठवां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार और 5वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों के साथ वैश्विक कारोबारी जुड़ाव को लेकर एक समझ है, जिसके वजह से वह अपने कारोबारी साझेदारों और वस्तुओं का विविधीकरण करने पर काम कर रहा है।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त पीटर एन वर्घेस द्वारा लिखित इंडिया इकनॉमिक स्ट्रैटजी टु 2035 में दोनों देशों के बीच और ज्यादा आर्थिक सहभागिता की वकालत की गई है, खासकर ऐसी स्थिति में जब भारत के कारोबारी विदेश में नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं और भारत सरकार उनका समर्थन कर रही है।

अब भारत ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया कारोबार के लिए सक्रिय है। मोरले ने भी कहा कि कृषि दिग्गज जैसे ग्रेनकॉर्प और ओलम ऑस्ट्रेलिया भारत में अपनी गतिविधियां तेज कर सकती हैं। कृषि कारोबार और इससे जुड़े क्षेत्र जैसे लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण प्रमुख क्षेतत्र हैं, जो आर्थिक समझौते की संभावना देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वित्त वर्ष 18 में 92.4 करोड़ डॉलर के चने और दालें व 12.563 करोड़ डॉलर का गेहूं भेजा था। लेकिन अगले साल भारत में दलहन की फसल अच्छी होने की वजह से निर्यात घट गया।

सौदे का इंतजार

पिछले साल नवंबर में क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी से भारत निकल गया था, उस समय ऑस्ट्रेलिया ने और ज्यादा उचित वातावरण बनाने पर जोर दिया था, जिससे भारत इस समझौते में शामिल हो सके। भारत को ऑस्ट्रेलिया के डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार माना जा रहा है।

लेकिन सूत्रों ने अब कहा कि लंबी सुस्ती के बाद दोनों देश एक बार फिर प्रस्तावित समग्र आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर कारोबारी बातचीत फिर शुरू कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पादों और मांस की भारत के बाजारों में पहुंच को लेकर बातचीत चल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपना सेवा निर्यात खोलने को लेकर असहज है। समझौते की राह में यह बड़ा रोड़ा है, जिस पर 2011 में बातचीत शुरू हुई थी।

13 दौर से ज्यादा की वार्ता के बाद सरकार अब एक बार फिर बातचीत का मन बना रही है और ऑस्ट्रेलिया को सकारात्मक संकेत दिए हैं।

पायलटों व नियंत्रकों द्वारा नशीली दवा सेवन की होगी जांच

अनीश फडणीस
मुंबई, 21 फरवरी

नियामकीय कदमों के तहत सुरक्षा में सुधार के लिए भारत में पायलटों व हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा ड्रग्स और साइको एक्टिव पदार्थों के सेवन की जांच की जाएगी। औचक जांच के अलावा भर्ती के पहले और दुर्घटनाओं के बाद भी इस तरह के परीक्षण किए जाएंगे।

शराब की जांच के लिए उड़ान से पहले पायलटों व केबिन क्रू की ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट किया जाता है। पिछले साल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस परीक्षण का दायरा बढ़ाकर ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों, इंजीनियरों और हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसी) तक कर दिया था। भारत के नियमों को वैश्विक मानकों की तर्ज पर करने के लिए डीजीसीए ने ड्रग्स और नशीले पदार्थों के परीक्षण हेतु पायलटों व एसीटी के रेंडम टेस्टिंग का प्रस्ताव किया था। जांच की प्रक्रिया को लेकर जीडीसीए ने आज मसौदा नियम जारी किए हैं।

डीजीसीए द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा डीजीसीए के अधिकारियों की निगरानी में रेंडम टेस्ट किया जाएगा। इन परीक्षणों में हर संस्थान के 10 प्रतिशत कर्मचारी हर साल शामिल होंगे। पहले चरण में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु और हैदराबाद के फ्लाइट क्रू और एटीसी की जांच की जाएगी।

डीजीसीए ने जारी किए मसौदा नियम

- डीजीसीए द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा डीजीसीए के अधिकारियों की निगरानी में रेंडम टेस्ट किया जाएगा
- इन परीक्षणों में हर संस्थान के 10 प्रतिशत कर्मचारी हर साल शामिल होंगे
- पहले चरण में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु और हैदराबाद के फ्लाइट क्रू और हवाई यातायात नियंत्रकों की जांच की जाएगी

इन परीक्षणों में शुरुआती परीक्षण और पुष्टि के लिए परीक्षण शामिल होगा। शुरुआती यानी स्क्रीनिंग टेस्ट एयरपोर्ट और एटीसी कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा और ऐसे परीक्षणों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जिन कर्मचारियों के टेस्ट पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें संवेदनशील सेवाओं से तब तक के लिए हटा लिया जाएगा, जब तक कि पुष्टि के परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आ जाती है।

अगर पुष्टि के लिए किया गया परीक्षण भी पॉजिटिव पाया जाता है तो कर्मचारी को पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इलाज कर रहे मनोचिकित्सक और संगठन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ही उसे काम पर वापस लिया जाएगा। दूसरी बार कानून का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

इसमें संलिप्त पाए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के पहले मेडिकल रिव्यू ऑफिसर की नियुक्ति इसकी समीक्षा करने के लिए किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, 'हम उद्योग में साइकोएक्टिव पदार्थों का परीक्षण नहीं करते हैं और हम उस खाई को पाटने का कवायद कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यह कवायद कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन व अन्य नियामकों की ओर से स्थापित उच्च मानदंडों का पालन किया जाए। हमें भरोसा है कि इससे हमारे सुरक्षा मानकों में सुधार होगा।'

कुमार ने कहा कि प्रस्तावित नियम यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन एविएशन सेप्टी एजेंसी द्वारा तय मानकों की तरह है।

(रॉयटर्स के साथ)

बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई कम

श्रेया जय
नई दिल्ली, 21 फरवरी

ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी तकनीकी शाखा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें देश में बिजली की मांग की रफ्तार सुस्त गति से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इसमें पहले जताए गए अनुमान से करीब 20 फीसदी की कमी आई है। यह परिणाम मांग अनुमानों में संशोधन किए जाने और ज्यादा सटीक नतीजे पर पहुंचने के लिए गणना की इकोनोमेट्रिक तरीके का इस्तेमाल करने के बाद सामने आया है।

अगस्त 2019 में तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध है लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। हर साल मार्च से मई के बीच मंत्रालय खुद ही एक अनुमान जारी करता है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि वह इन आंकड़ों को अपना आधिकारिक रुख बनाना नहीं चाहता है। ऊर्जा मंत्रालय को भेजी गई एक विस्तृत प्रश्नावली के जवाब में उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

खारिज किया अनुमान

- ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी तकनीकी शाखा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें देश में बिजली की मांग की रफ्तार सुस्त गति से बढ़ने का अनुमान जताया
- सीईए के मुताबिक ऊर्जा की मांग 5 फीसदी की सुस्त दर से बढ़ेगी जो पहले की रिपोर्टों के मुकाबले कम

परामर्श फर्म केपीएमसी के साथ सीईए की ओर से तैयार की गई नई रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा जरूरत की वृद्धि दर 2021-22 से 2026-27 तक 5.22 फीसदी बताई गई है। यह इसी दौरान 8 फीसदी की आशावादी जीडीपी दर के आधार पर बताई गई है।

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2021-22 के दौरान 1,477 अरब यूनिट ऊर्जा की मांग रह सकती है जो 2026-27 में 1,905 अरब यूनिट पर पहुंच सकती है। इससे पहले की रिपोर्ट में समान अवधि के लिए ऊर्जा की मांग 1,566 अरब यूनिट और 2,047 अरब यूनिट बताई गई थी। हालांकि, सरकार ने उसे भी स्वीकार नहीं किया था। अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान भारत की ऊर्जा मांग 951 अरब यूनिट रही थी।

सीईए ऊर्जा मंत्रालय की तकनीकी शाखा है और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लघु और दीर्घ अवधि की मांग अनुमान निर्धारित करने और नीति नियोजन पर सलाह देने की बात कही गई है। हर साल सीईए इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के जरिये देश की मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर दीर्घ अवधि की विद्युत मांग का निर्धारण करता है।

2016 में आए पिछले ईपीएस के बाद विभागों के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि उसमें मांग में कमी आने का अनुमान जताया गया था। तब सीईए ने 2022 तक विद्युत मांग का अनुमान 289 गीगावॉट से घटाकर 239 गीगावॉट कर दिया था। 2018 की रिपोर्ट में इसे और कम कर 225 गीगावॉट कर दिया गया।

इंडियन बैंक एटीएम में 2,000 रुपये के नोट करेगा बंद

गिरीश बाबू
चेन्नई, 21 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपनी शाखाओं को कैश रीसाइकलर और एटीएम में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोट डालना तत्काल प्रभाव से बंद करने की सलाह दी है। इस संबंध में कहा गया है कि ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे खुदरा दुकानों में अधिक मूल्य मूल्यवर्ग के नोटों का आदान-प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं।

बैंक के डिजिटल बैंकिंग अनुभाग द्वारा 17 फरवरी को जारी एक परिपत्र के अनुसार 1 मार्च, 2020 को सभी एटीएम और कैश रीसाइकलर में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग की नकदी का वितरण रोक दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस निर्णय के तहत बैंक के चैनलों द्वारा आम लोगों को मुख्य रूप से 500 रुपये मूल्यवर्ग से कम वाले नोट दिए जाएंगे, जबकि शाखाएं सामान्य रूप से 2,000 रुपये सहित करेंसी नोटों देती रहेंगी।

बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के करेंसी नोटों के वितरण से ग्राहकों को असुविधा हो रही है क्योंकि वे खुदरा दुकानों में अधिक मूल्यवर्ग के नोटों का आदान-प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वे एटीएम से निकाले गए 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को कम मूल्यवर्ग वाले नोटों से बदलवाने के लिए शाखाओं में आ रहे हैं।

एटीएम के जरिय केवल कम मूल्य वाले करेंसी नोटों का ही वितरण किया जाएगा। आउटसोर्स किए गए एटीएम और कैश रिप्लेसमेंट एजेंसियों को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट जमा नहीं करने की सलाह दी जाएगी। हालांकि कैश रीसाइकलर जमा किए जाने वाले लेनदेन के दौरान ग्राहकों से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग वाले नोट स्वीकार करना जारी रखेंगे।

सही करदाताओं का भी अटका धन: बादल

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 21 फरवरी

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने 'वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन में मनमानी' को लेकर राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय को पत्र लिखा है। यह पत्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के 40,000 करोड़ रुपये फंसे होने को लेकर लिखा गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि कारोबारी पहले ही अर्थव्यवस्था सुस्त होने की वजह से पीड़ित हैं और टैक्स क्रेडिट में नकदी फंस गई है, जिससे उन्हें कार्यशील पूंजी के संकट से जूझना पड़ रहा है।

बादल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी करने वालों के मामले में टैक्स क्रेडिट रोकने के लिए अधिकृत किया था, न कि ऐसे मामलों में क्रेडिट रोकने की अनुमति दी थी कि किसी स्थापित विश्वसनीयता वाले करदाता का पैसा रोक दिया जाए।

शुक्रवार को पत्र में लिखा गया है, 'इसका मकसद साफ था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि फर्जी इनवाइस बनाकर रातोंरात भाज जाने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। जो ईमानदार करदाता हैं और जिनकी विश्वनीयता स्थापित है, उनके लिए यह प्रावधान नहीं किया गया था।'

फाइलिंग और रिटर्न में मिलान न होने की वजह से 2,000 से ज्यादा कंपनियों का 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी क्रेडिट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रोक रखा है।

बादल ने पत्र में लिखा है, 'ऐसा लगता है कि सभी करदाताओं का टैक्स क्रेडिट रोक दिया गाय है, जिन मामलों में जीएसटीआर-2ए और सीएसटीआर 3बी में कुछ अंतर पाया गया है। केंद्रीय कर अधिकारियों ने उन मामलों में भी कार्रवाई की है, जहां करदाता इस मकसद के लिए सहमति वाले प्रोटोकॉल से हटे हैं।'

क्लीयरटैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि मिलान न करा पाने वाले करदाताओं को नोटिस के प्रबंधन को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'आईटीसी के लिए जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी को सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आईटीसी रोक दिया जाता है तो कारोबार प्रभावित होगा और नोटिस की वजह से समस्या और बढ़ेगी। इस तरह के कुछ करदाता हमारे पास समाधान के लिए आए हैं।'

राजस्व सचिव को पंजाब से पत्र

इनपुट टैक्स क्रेडिट के 40,000 करोड़ रुपये फंसे होने को लेकर लिखा पत्र

- पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इनपुट क्रेडिट रोकने की सहमति फर्जी इनवाइस रोकने को लेकर बनी थी
- मंत्री के मुताबिक ईमानदार करदाताओं के भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रोका गया, जिससे उन्हें पूंजी का संकट

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 6

नाराजगी का कारण!

मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपनी किताब, बैकस्टेज: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ इयर्स, में लिखा है कि कैसे 40 वर्ष पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ईशर ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आकर्षक करियर छोड़कर वॉशिंगटन से भारत लौटने का निर्णय लिया था। मोंटेक वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए थे और ईशर एक थिंक टैंक से जुड़ गई थीं। दोनों का वेतन कम रहा होगा और उनका घर भी औसत सरकारी आवास रहा होगा लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। दोनों राजधानी के पावर कपल (शक्तिशाली युगल) के रूप में स्थापित हुए, यानी जिंदगी ने किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति भी की। कई अन्य अर्थशास्त्री भी वापस आए। मनमोहन सिंह, बिमल जालान, विजय केलकर, शंकर आचार्य, राकेश मोहन आदि ऐसे ही कुछ नाम हैं। ये सभी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पढ़कर और श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में काम करके आए थे। वे अगले तीन-चार दशक के दौरान देश की आर्थिक नीति के शीर्ष निर्माता रहे या उसे प्रभावित करने वालों में प्रमुख रहे, मोंटेक की तरह उनमें से कई उच्च पदों पर पहुंचे और काफी प्रतिष्ठित हैं। इसके अलावा लुटियन क्षेत्र में बंगला और वह सामाजिक कद उन्हें मिला है जो किसी भी अन्य जगह पर मुश्किल होता। इस सप्ताह के आरंभ में मोंटेक की किताब के लोकार्पण के अवसर पर यह सवाल उठा था कि आखिर उनके जैसे लोग आज वापस भारत में अपनी जड़ें जमाने क्यों नहीं आ रहे? जो लोग हाल के दिनों में वापस आए भी हैं वे ग्रीन कार्ड त्यागना नहीं चाहते ताकि वापसी की राह बची रहे। अरविंद पानगड़िया, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति इनमें शामिल हैं। एक उत्तर यह है कि भारत में हमेशा से आर्थिक शरणार्थी रहे हैं और उन्हें जहां भी रोजगार मिला वे गए (पश्चिम एशिया और सिंगापुर में) या फिर बेहतर शिक्षा जिसका सीधा संबंध अच्छे करियर से है। कई लोग शानदार काम कर रहे हैं, वैश्विक टेक कंपनियों के मुखिया हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। परंतु इस कहानी का एक स्याह पहलू भी है। हालांकि भारत अब सन 1980 और 1990 के दशक जैसा गरीब देश नहीं रह गया है और कुछ वर्ष पहले वह निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश में बदल चुका है लेकिन वह क्यूबा की तरह एक आर्थिक कारागार में तब्दील हो गया। वहां उच्च वेतन के साथ करियर में ज्यादा विकल्प मौजूद हैं, महंगी कारों और उपभोक्ता वस्तुओं की भरमार है, आधुनिक अस्पताल और नए उदारवादी कला महाविद्यालय हैं तथा बिना रिजर्व बैंक की अनुमति और आठ डॉलर की रकम के बंधन के आजादी से विदेश भ्रमण की इजाजत है। इसके बावजूद यह रहने और काम करने की दृष्टि से कम आकर्षक देश रह गया है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

तमाम कारोबारी दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। वे अन्य बाजारों में निवेश कर रहे हैं जहां जीवन आसान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कौशल वाले अमीर पेशेवर अपना पैसा भी अपने साथ ले जा रहे हैं। यही कारण है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की बात कही। हो सकता है वे कर आतंक से बचने के लिए ऐसा कर रहे हों, उन्हें आर्थिक अवसर अपेक्षा से कम मिल रहे हों या वे एक पांव भारत में तो दूसरा विदेश में रखना चाहते हों क्योंकि भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं सर उठा रही हैं। वजह चाहे जो हो पुराने आर्थिक शरणार्थियों की जगह अब नए सुस्थापित लोगों के देश छोड़ने ने ले ली है। या शायद वे देश की अनाकर्षक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से दूरी बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कम आबादी वाले देशों में अचानक भारतीय प्रवासियों की बाढ़ आ गई है। एक सवाल यह भी है कि क्या हमारे अर्थशास्त्रियों को पीछे मुड़कर संतुष्टि के साथ देखना चाहिए, या नाराजगी के साथ? यकीनन सन 1991 के सुधार जैसे मोड़ आए, एक दशक पहले जैसी तेज वृद्धि देखने को मिली और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। परंतु हमें सुधारों के लिए सन 1991 तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि मोंटेक लिखते हैं, आईएमएफ प्रमुख ने सन 1988 के आरंभ में राजीव गांधी को चेताया था कि संकट बढ़ रहा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भारत में दूरसंचार क्रांति कोई विशेष बात नहीं थी। अन्य देशों में भी इस क्षेत्र में नाटकीय सुधार हुआ। न ही तेज वृद्धि कोई विशिष्ट बात थी। सन 2004-08 के बीच उभरते बाजारों की औसत वृद्धि दर 7.9 फीसदी रही। चीन तो छोड़िए आज भारत बांग्लादेश और वियतनाम से भी पीछे है। थाई मुद्रा बहत का मूल्य 2.25 रुपये है। सन 1991 में यह इसका आधा थी।

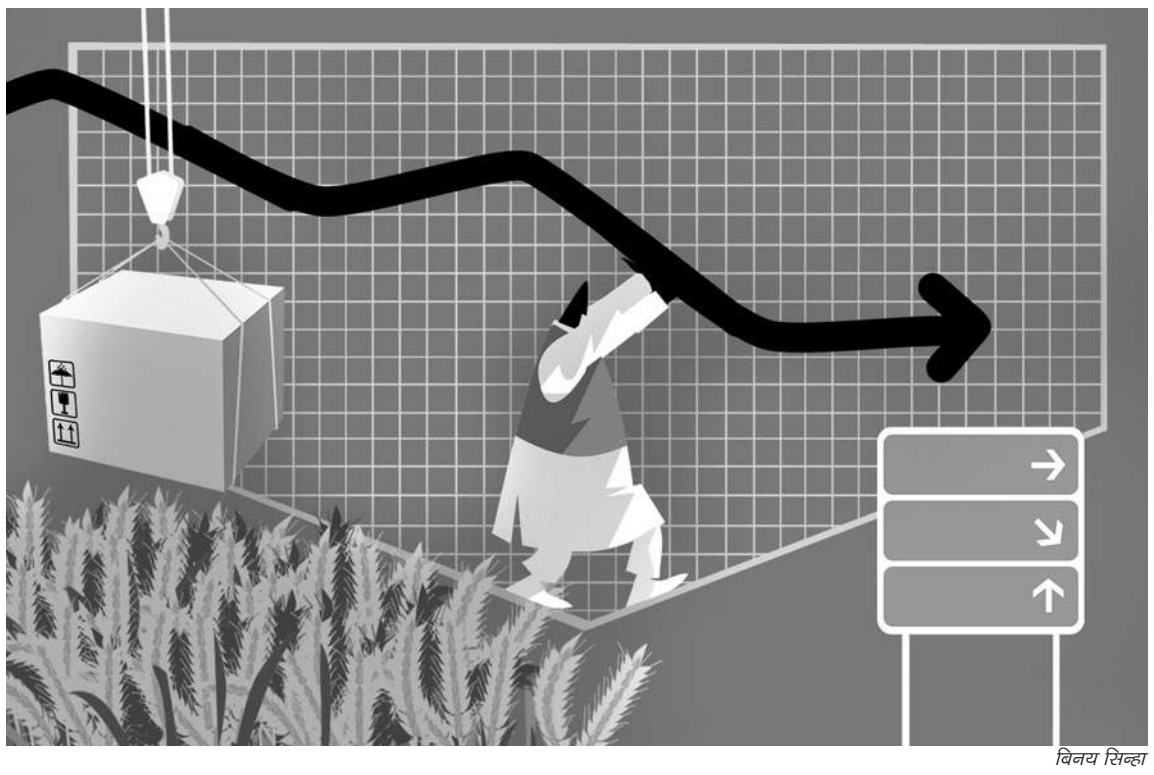

बिनय सिन्हा

संस्थागत सुधार से बनेगी बात

सरकार को अब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष पेशकदमी से पीछे हटकर बाजार की विसंगतियां दूर करने और सामाजिक विसंगतियां समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विस्तार से समझा रहे हैं नितिन देसाई

इन दिनों अक्सर यह सुनने में आता है कि वृद्धि बहाल करने के लिए अहम नीतिगत सुधार करने होंगे। विजय केलकर और अजय शाह ने अपनी शानदार पुस्तक इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक: द आर्ट ऐंड साइंस ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी (पेंगुइन रैंडम हाउस 2019) में नीति निर्माण की प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त दृष्टिकोण पेश किया है जिसे हर नीति निर्माता और टीकाकार को पढ़ना चाहिए। केलकर और शाह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जीडीपी वृद्धि पर संस्थागत निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सन 1950-51 से देश की जीडीपी सन 1969-70, 1987-88, 1999-2000 और 2010-11 में दुगनी होती गई। क्या तत्कालीन घरेलू राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल के मद्देनजर उस समय नीतियों में भी चार बार बदलाव देखने को मिला?

नेहरू युग की नीति अपने समय के हिसाब से ठीक थी क्योंकि उस समय व्यापक उद्यमिता का अभाव था, पूंजी की कमी थी और तकनीकी क्षमताओं का अभाव था। केलकर और शाह उस समय के लिए इस नीति का मूल्य समझते हैं खासतौर पर तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता कायम करने के मामले में (जो आज हमारी मददगार है) और उद्यमिता का आधार बढ़ाने में। परंतु उनके बुनियादी नियम के मुताबिक देखें तो बड़ा नीतिगत बदलाव और संस्थागत सुधार 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के आरंभ में हो जाना चाहिए था।

उस वक्त कृषि और खाद्य संरक्षा पर जोर दिया गया जो वांछित था। परंतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में एक समाजवादी नीति वाला बदलाव, खाद्यान्न कारोबार पर राज्य का नियंत्रण और कोयला एवं तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, मजबूत एकाधिकारवादी प्रतिबंध और गरीब विरोधी नीतियां आदि जल्दी ही खेद की वजह बन गईं।

कहा जा सकता है कि यदि वाम रुझान नहीं होता तो देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सन 1980 के दशक के अंत में व्यापक उदारीकरण के लिए तैयार होती। संभवत: भ्रमित राजनीति, कांग्रेस के विभाजन, आपातकाल और निष्प्रभावी जनता सरकार के कारण ऐसा नहीं हुआ। सन 1960 के दशक के मध्य के सूखे और 1970 के दशक में तेल के झटकों ने भी आर्थिक संभावनाओं को क्षति पहुंचाई।

जो सुधार 1960 के दशक के आखिर में या 1970 के दशक के आरंभ में होने थे वे एक दशक बाद जैसे तैसे शुरू हुए। परंतु वृद्धि अभी भी सरकारी क्षेत्र पर निर्भर थी। सन 1980 के दशक में तयशुदा निवेश में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो गई। केलकर और शाह के रुख के अनुरूप नीतिगत सुधारों में बड़े संस्थागत बदलाव की बात करें तो वह सन 1991 में देखने को मिला जब निवेश और व्यापार नियंत्रण समाप्त किया गया। वित्तीय क्षेत्र में ऐसे सुधार किए गए जिन्होंने पूंजी बाजार को उदार बनाया और अर्थव्यवस्था को बहिर्मुखी बनाया। जीवंत वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वस्थ राजनीतिक माहौल प्रभावी नीतिगत नेतृत्व से भी मदद मिली। 1990 के दशक के सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के बीच सुसंगतता कायम करना था। यह बदलाव काफी तीक्ष्ण था क्योंकि तयशुदा निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। यह 1980 के दशक के 50 फीसदी से बढ़कर 1990 के दशक में 65 फीसदी और नई सदी के पहले दशक में 75 फीसदी हो गई।

केलकर और शाह का नियम सुझाता है कि अब बड़े नीतिगत और संस्थागत बदलावों का वक्त आ गया है और इन्हें सहस्राब्दी की शुरुआत में और पहले दशक के अंतिम वर्षों में अंजाम दिया जाना चाहिए था। बड़े बदलावों और कुछ बुनियादी सुधारों मसलन जीएसटी और आईबीसी को पूरा किया गया लेकिन अभी भी ध्यान केंद्र सरकार और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र पर ही केंद्रित है।

मेरी दृष्टि में हमें जिन संस्थागत और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है वे कॉर्पोरेट क्षेत्र के नियामकीय दायरे से बाहर हैं। हमें कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत बदलावों और सरकार के संगठन में अहम सुधारों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए लेकिन उनसे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसे में नीति निर्माताओं को कुछ गहन सवालों के जवाब देने होंगे।

क्या एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस स्थिति में किफायती तरीके से काम कर सकती है जब अधिकांश वित्तीय संस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित हों और उनके प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप होता हो? क्या प्रबंधन में मामूली बदलाव पर्याप्त हैं? या हमें अधिक कड़े उपायों, मसलन निजीकरण की आवश्यकता है? क्या दो मुख्य अनाजों का समर्थन करने वाली कृषि नीति जो सन 1960 और 1970 के दशक में उपयुक्त रही थी वह कृषि आय और वृद्धि की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए भी पर्याप्त है? क्या सरकार को प्रत्यक्ष भागीदारी से दूर रहना चाहिए? किसानों को कतिपय प्रतिबंधों से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है कि वे अपनी सामग्री कहां और किसे बेचेंगे तथा उन्हें निर्यात समेत उच्च मूल्य उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है?

क्या केंद्रीय विनियमन और प्रबंधन वाली व्यवस्था उस वक्त उचित मानी जा सकती है जबकि आपूर्ति के स्रोतों में निजी उत्पादन कंपनियां और बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता शामिल हों? हम बिजली आपूर्ति और मांग के बाजार में द्विपक्षीय लेनदेन से थोक बाजार लेनदेन का रुख कैसे करेंगे?

क्या सरकारी शिक्षा तंत्र में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण को कम किया जा सके और स्थानीय संस्थाओं, माता-पिता और छात्रों के प्राधिकार मजबूत किए जा सकें। इसके लिए शिक्षा को मिलने वाला सरकारी समर्थन संस्थानों को प्रत्यक्ष अनुदान या छात्रों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में दिया जा सकता है। उस स्थिति में गुणवत्ता सुधार का दबाव बनाना अधिक आसान होगा। क्या हम छोटे उद्यमों के साथ भेदभाव वाले आचरण की धारणा समाप्त कर सकेंगे और छोटे रहने से जुड़े प्रोत्साहन समाप्त कर सकते हैं?

भारत अब उस चरण से आगे निकल चुका है जहां उसे माई-बाप सरकार की जरूरत थी। उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी जटिल और बहिर्मुखी है कि उसका केंद्रीय प्रबंधन करना मुश्किल हो चला है।

देश की जनता और उद्यम अब इतने सक्षम हैं कि उन्हें सरकारी एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे बाजार विसंगति दूर करने, पर्यावरण पर प्रभाव या सामाजिक विसंगतियों मसलन बढ़ती असमानता आदि से निपटने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें देश में नीतिगत और संस्थागत सुधारों के क्षेत्र में इसी एजेंडे पर काम करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस नेतृत्व में आंतरिक भ्रम से कार्यकर्ता भी हो रहे भ्रमित

प्रबंधन का सिद्धांत कहता है: नेतृत्व करो, अनुसरण करो या मार्ग से हट जाओ। राहुल गांधी इनमें से किसका पालन कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। उनका अनिर्णय देश के मुख्य विपक्षी दल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अत्यंत खराब प्रदर्शन और राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी को अस्थायी बनाया गया था। उस बात को छह महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। सोनिया गांधी की नियुक्ति पर संगठन की मुहर अभी लगनी शेष है (यह वैसे भी असंवैधानिक है क्योंकि पार्टी संविधान में अस्थानीय या अंतरिम अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है)। कांग्रेस का अंतिम पूर्ण सत्र 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। सामान्य तौर पर पूर्ण सत्र हर तीन वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। परंतु हमें सुनने को मिल रहा है कि इस समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि खुलकर कहें तो कांग्रेस में भारी गड़बड़ी चल रही है और पार्टी सामूहिक सोच के साथ ही खुद को संकट से बाहर निकालने पर विचार कर रही है।

राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि सत्ता जहर है। परंतु वह भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। पूर्ण सत्र को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि 'राहुल लाओ, देश बचाओ' जैसा अभियान छेड़ा जा सके और वह एक बार पुन: कांग्रेस अध्यक्ष बनें। ध्यान रहे कि उनसे पहले उनके पिता, उनकी मां, दादी और नाना तक इस पद पर रह चुके हैं। उनके सभी रिश्तेदार मजबूत मस्तिष्क वाले लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपनी पहचान छोड़ी और उसकी दिशा तय करने में मदद की। परंतु राहुल के बारे में कोई नहीं जानता।

राहुल गांधी अलग-अलग अवसरों पर इस बात के प्रति लगाव दर्शाते रहे हैं कि कांग्रेस कैसी दिखनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में ज्यादा लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसे में पार्टी संगठन से कहा गया कि वह प्राइमरीज का आयोजन करे जहां ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं के ज्यादा वोट पाने वाले नेताओं को ही अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का टिकट मिलेगा। प्राइमरीज में जीत हासिल करने वाले लोगों में से कई पुराने कांग्रेस नेताओं के बच्चे थे। दूसरी या तीसरी पीढ़ी के कांग्रेसियों की तरह उन्हें भी वफादारी और संरक्षण हासिल था। ऐसे में प्राइमरीज में हारने का मतलब था, पारिवारिक विरासत गंवाना। ऐसे में जो लोग पार्टी का यह आंतरिक चुनाव जीतने में कामयाब रहे, वहीं वे असली चुनाव में हार गए। ऐसे में कांग्रेस को मां-बेटे की पार्टी से अलग छवि देने का प्रयास नाकाम रहा।

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

सच तो यही है कि कांग्रेस के लिए परिवार ही अपील की आखिरी अदालत है। वही बराबरी वालों में सबसे श्रेष्ठ है। यदि गांधी परिवार नहीं होगा तो सभी नेता समान होंगे। यदि सभी नेता समान होंगे तो कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है। यानी हर बार जब परिवार पार्श्व में गया तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ

इसके बाद सवाल यह भी था कि पार्टी को आखिर किसे चुनना चाहिए। राहुल को? या सोनिया को? या फिर प्रियंका को? और भविष्य की संभावना, रॉबर्ट? पार्टी को धर्मनिरपेक्षता की राह पर आगे बढ़ना चाहिए? या समाजवाद की? या कुछ-कुछ दोनों? जाहिर है इससे कुछ नहीं होना था क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक काट कोई व्यक्ति ही हो सकता है, कोई विचार या मुद्दा नहीं?

इस विषय पर भी अत्यधिक भ्रम की स्थिति है। राहुल कहते हैं कि वह पूरे मसले से बाहर हैं लेकिन ऐसा है नहीं। उनके द्वारा चुने हुए लोग ही प्रियंका के सलाहकार हैं। अहम नियुक्तियों में उनके सलाहकारों की बात सुनी जा रही है। लेकिन बात तो उनकी भी सुनी जा रही है जो सोनिया के वफादार होने का दम भरते हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि आखिर निर्णय कौन ले रहा है?

जब जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल को सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों की सराहना करनी चाहिए (उदाहरण के लिए उज्ज्वला) तो वीरप्पा मोइली और कपिल सिब्बल ने तत्काल उनकी बात का विरोध किया। जब मिलिंद देवड़ा ने आम आदमी पार्टी के राजकोषीय विवेक के लिए उसकी तारीफ की तो अजय माकन ने उनका गला पकड़ लिया और कहा कि वह कांग्रेस छोड़ दें। ठीक इसी तरह शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पी चिदंबरम की आलोचना की क्योंकि वह दिल्ली चुनाव में आप की जीत से उत्साहित थे। इस दौरान सामान्य कर्मचारी असहाय होकर देखते रहे। काफी हद तक टेनिस मैच के दर्शकों की तरह। कुछ तो खुलकर कहते हैं कि इधर उधर देखते-देखते उनकी गरदन में दर्द होने लगा है।

सच तो यही है कि कांग्रेस के लिए परिवार ही अपील की आखिरी अदालत है। वही बराबरी वालों में सबसे श्रेष्ठ है। यदि गांधी परिवार नहीं होगा तो सभी नेता समान होंगे। यदि सभी नेता समान होंगे तो कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है। यानी हर बार जब परिवार पार्श्व में गया तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ।

यह बात हमें एक असहज करने वाले नतीजे पर पहुंचाती है। वह यह कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक का नेतृत्व केवल एक परिवार कर सकता है। केवल उस परिवार के पास ही यह शक्ति है कि वह खुद को उस जवाबदेही से मुक्त कर सके। परंतु फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। भाजपा में बहुत खामोशी से इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या अब वक्त आ गया है कि सन 2024 के चुनाव के पहले इसे व्यक्तियों की लड़ाई से विचारों की लड़ाई में तब्दील किया जाए। जहां तक कांग्रेस की बात है, वह न तो व्यक्तियों को लेकर स्पष्ट है और न ही विचारों को लेकर।

कानाफूसी

सबको आमंत्रण

जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की बात सामने आई है, एक सवाल सबके मन में है कि अहमदाबाद में 24 फरवरी को आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है या नहीं। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में यह कार्यक्रम डॉनल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसने कहा कि यही संगठन आमंत्रित व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करेगा। अहमदाबाद के नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब दो लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने उन्हें बताया कि स्टेडियम और एयरपोर्ट के बीच करीब 70 लाख लोग स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे यह बहुत रोमांचक होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें आशा है कि यह पूरा कार्यक्रम सबके लिए दिलचस्प रहेगा। बहरहाल अहमदाबाद नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि 70 लाख तो पूरे अहमदाबाद की आबादी है।

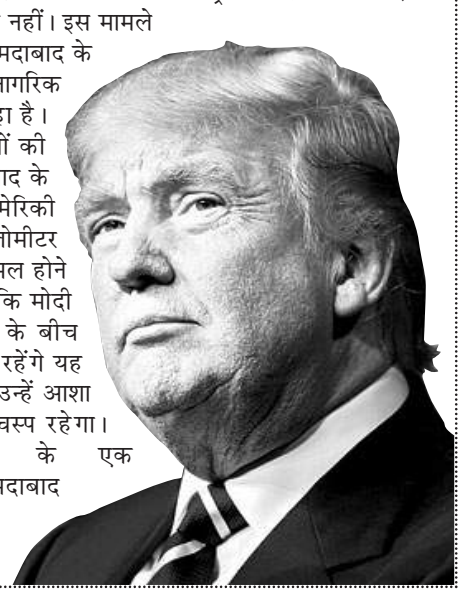

आपका पक्ष

ट्रंप की भारत यात्रा का औचित्य?

अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रंप भारत की अपनी पहली यात्रा पर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस यात्रा में ही ऐसे कुछ फैसले लेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और विश्वव्यापी समस्याओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भारत और अमेरिका के बीच महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। मोदी-ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के बीच कुछ नए फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। यह दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होने के संकेत हैं, लेकिन भारत के प्रति अमेरिका आने वाले समय में कैसा रुख अख्तियार करेगा, यह भारत की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा और ट्रंप का हमारे देश के प्रति प्रेम कितने दिनों तक कामयाब रहेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी दो मुख्य समस्याएं आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन है। इन दोनों समस्याओं के लिए भी अमेरिका, भारत के साथ खड़ा नहीं दिखता है। अव्वल तो यह कि आतंकवाद के प्रति अमेरिका दोगली नीति अपनाता आया है। दूसरा कुछ समय पहले ट्रंप ने पेरिस समझौते से भागने का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया था, जबकि भारत इन दोनों मुख्य समस्याओं को विश्वमंच पर उठाता आया है। अमेरिका की कथनी करनी में फर्क है। वह भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात तो करता है, लेकिन वह जब अपने स्वार्थ देखता है तो इसमें भारत के हितों को नहीं देखता है। ऐसे में भारत को ट्रंप के आगमन से कितना फायदा होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में होगा *-पीटीआई*

एनआरआई के लिए कर समस्या

आयकर के वर्तमान नियम एनआरआई आयकरदाता के लिए बहुत ही जटिल हैं और इसके लिए उन्हें कर विशेषज्ञ की महंगी सेवाएं लेना अनिवार्य हो जाता है। इसमें विशेषकर किराये पर कर कटौती बहुत ही जटिल है। संबंधित फॉर्म 27 व ट्रेसिंस से फार्म 16ए किरायेदार बिना कर विशेषज्ञ के नहीं निकाल सकता है और इसके लिए भारी फीस देनी पड़ती है, जिस वजह से किरायेदार नहीं मिलते और मकान खाली रहते हैं। किराये की आमदनी कितनी भी कम हो टीडीएस 31.22 प्रतिशत की दर से कटता है। आयकर अधिकारी के पास प्रतिवर्ष इसकी दर कम कराने के लिए आवेदन करना पुन: खर्चीला और जटिल है। इन कारणों से मध्यम वर्गीय एनआरआई त्रस्त व परेशान हैं। आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय को इस जटिलता को कम करना चाहिए।

दिलीप, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सोने के दामों में 2 प्रतिशत उछाल

सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा सोना, ग्राहकों ने बनाई खरीद से दूरी, खुदरा दुकानों से ग्राहक रहे नदारद

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 21 फरवरी

सोना शुक्रवार को 2 प्रतिशत की उछाल के साथ अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। पीली धातु में जबरदस्त उछाल के कारण खुदरा आभूषण विक्रेताओं के यहां स्टोर खाली देखे गए। एक्सचेंज से जुड़े ग्राहकों ने अधिक निर्माण शुल्क के कारण अपने लेनदेन टाल दिए। मुंबई के जवेरी बाजार में मानक सोना हाजिर कारोबार में 42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से मिल रहा था। महाशिवरात्रि पर अवकाश के कारण जवेरी बाजार में ज्यादातर दुकानें बद मिलीं और जो दुकानें खुली रहीं, वहां ग्राहक नहीं दिखे।

जवेरी बाजार के सराफा कारोबारी उमेदमल तिलोकचंद जवेरी के निदेशक कुमार जैन ने कहा,'सोने की कीमतों में तेजी के बाद शायद आज कारोबार नहीं दिखा। मासिक जमा योजना और एक्सचेंज ट्रेडेड ग्राहक भी नदारद दिखे।' कैलेंडर वर्ष 2020 में अब तक सोने की कीमतों में 8.5 प्रतिशत तक की तेजी आई है। इसी तरह, पिछले कैलेंडर वर्ष भी सोना 26 प्रतिशत तक उछला था। लंदन के बेंचमार्क हाजिर बाजार में शुरुआती दौर में सोना 1,639 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले सात वर्षों का उच्चतम स्तर है। सोने में धीरे-धीरे लेकिन सतत बढ़ोतरी के मद्देनजर अग्रणी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनियों और निवेशकों ने पीली धातु में और तेजी आने का अनुमान जताया है। यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मुख्य कार्याधिकारी फ्रैंक होल्म्स ने सोने की कीमतें 1,900 डॉलर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने निवेशकों को अधिक सोना एवं चांदी खरीदने की सलाह दी।

केडिया कमोडिटी के प्रबंध निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'ब्याज दरों में कमी से सोने की कीमतों को हमेशा मदद मिली है। ब्याज दरों को लेकर आए दिन बनी अनिश्चितताओं के मद्देनजर निवेशक सोने में निवेश को लेकर अधिक उत्साहित रहते हैं।' दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को अमेरिकी शेयरों में तेजी थम गई और विभिन्न दूसरी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती देखी गई। आर्थिक प्रोत्साहनों के कारण जापानी मुद्रा येन में कमजोरी दिखी और निवेश का एक सुरक्षित जरिया होने के इसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो गए। मंगलवार के बाद येन के मुकाबले डॉलर में करीब 2 प्रतिशत तक तेजी आई है और पिछले 10 महीनों में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा यूरो के मुकाबले तीन वर्ष के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।

इस बीच, चीन और दुनिया के अन्य देशों में कोरोनावायरस के मामलों में कमी देखी गई है, जिससे से वैश्विक स्तर पर गतिविधियां तेजी होनी शुरू हो गई हैं। अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए चीन के प्रयासों के बाद तेल कीमतों में तेजी आई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेस में सहायक निदेशक किशोर नार्णे ने कहा कि सोना आने वाले समय में प्रति 10 ग्राम 45,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।

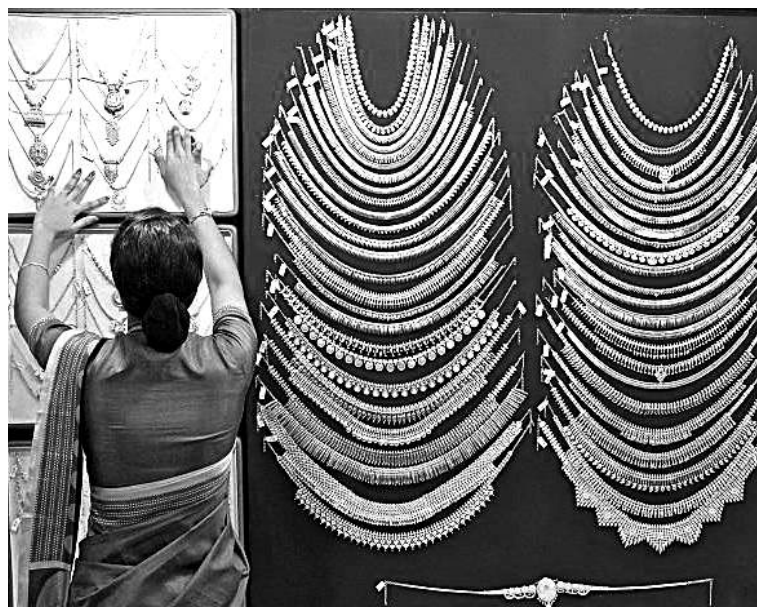

सोने में चमक

- कैलेंडर वर्ष 2020 में अब तक सोने की कीमतों में 8.5 प्रतिशत की तेजी आई
- पिछले कैलेंडर वर्ष भी सोना 26 प्रतिशत तक उछला था
- लंदन के बेंचमार्क हाजिर बाजार में शुरुआती दौर में सोना 1,639 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले सात वर्षों का उच्चतम स्तर है।
- मंगलवार के बाद येन के मुकाबले डॉलर में करीब 2 प्रतिशत तक तेजी आई है और पिछले 10 महीनों में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया
- अमेरिकी मुद्रा यूरो के मुकाबले तीन वर्ष के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया

सोने के दाम

दिन	रुपये/10 ग्राम
27 जनवरी	40,651
28 जनवरी	40,493
29 जनवरी	40,302
30 जनवरी	40,684
31 जनवरी	40,628
3 फरवरी	40,654
4 फरवरी	40,443
5 फरवरी	40,049
6 फरवरी	40,336
7 फरवरी	40,503
10 फरवरी	40,575
11 फरवरी	40,461
12 फरवरी	40,421
13 फरवरी	40,603
14 फरवरी	40,617
17 फरवरी	40,701
18 फरवरी	40,970
19 फरवरी	41,469
20 फरवरी	41,575
21 फरवरी	42,400

स्रोत- आईबीजेए
संकलन- बीएस रिसर्च

भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत लाभों को वापस लिया

परिधान क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन योजना

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 21 फरवरी

सरकार ने परिधानों और कपड़े से बने अन्य उत्पादों के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य का एक प्रतिशत अतिरिक्त अनौपचारिक (एड हॉक) प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की है। यह योजना ऐसे समय में आई है, जब ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के अंतर्गत लाभों को वापस ले लिया गया है।

निर्यातकों का कहना है कि अगर राज्य और केंद्रीय कर एवं शुल्क योजना (आरएससीटीएल) की छूट राज्य शुल्कों (आरओएसल) और एमईआईएस की छूट से कम होगी तो यह प्रोत्साहन जोड़ दिया जाएगा। सरकार ने इस प्रोत्साहन के लिए जनवरी के मध्य में अधिसूचना जारी की थी और अब दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह मुख्य रूप से 7 मार्च, 2019 से एमईआईएस हटाए जाने के बाद हुए नुकसान (यदि कोई हो) की भरपाई के लिए है।

चूंकि आरओएसएल और एमईआईएस आरओएससीटीएल के साथ ही उपलब्ध थे, इसलिए कई निर्यातकों की लागत पर इन दोनों का असर पड़ रहा था। निर्यातकों ने कहा कि इस बारे में सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

सरकार ने परिधानों और कपड़े से बने अन्य उत्पादों पर राज्य के मूल्य संवर्धित कर (वैट) तथा राज्य के अन्य करों का बोझ कम करने के लिए आरओएसएल को अधिसूचित किया है। चूंकि कुछ खास राज्य एवं केंद्रीय शुल्कों में छूट नहीं थी, इसलिए मार्च 2019 में कपड़ा मंत्रालय ने उत्पादों के निर्यात पर विभिन्न राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट के लिए आरओएससीएलटी को अधिसूचित किया है।

जनवरी 2020 में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आरओएससीएलटी की शुरुआत के बाद एमईआईएस के तहत दिया जाने वाला लाभ वापस लेने का फैसला किया था। मार्च 2019 तक रहने वाले आरओएसएल के तहत छूट का भुगतान निर्यातकों के बैंक खातों में किया जाता था। हालांकि आरओएससीएलटी और इस अतिरिक्त अनौपचारिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह छूट एमईआईएस के तहत दी जाने वाली छूट की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (पावती-पत्र) के रूप में प्रदान की जाएगी।

इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभ एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप में दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल सीमा शुल्कों और केंद्रीय उत्पाद शुल्कों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत जारी यह स्क्रिप पूरी तरह से हस्तांतरणीय होगी।

कपड़ा मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि आरओएससीएलटी का लाभ 7 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' (एलईओ) वाले परिधानों और कपड़े से बने अन्य उत्पादों के लिए उपलब्ध होगा, जबकि अतिरिक्त अनौपचारिक प्रोत्साहन योजना का लाभ 7 मार्च, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक एलईओ वाले निर्यात के लिए उपलब्ध होगा।

उद्योग के सूत्रों के अनुसार परिधान क्षेत्र पर आरओएसएल, जीएसटी और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के तहत सरकार की ओर से करीब 7,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

- सरकार ने इस प्रोत्साहन के लिए जनवरी के मध्य में अधिसूचना जारी की थी और अब दिशा-निर्देश जारी किए
- यह मुख्य रूप से 7 मार्च, 2019 से एमईआईएस हटाए जाने के बाद हुए नुकसान (यदि कोई हो) की भरपाई के लिए है

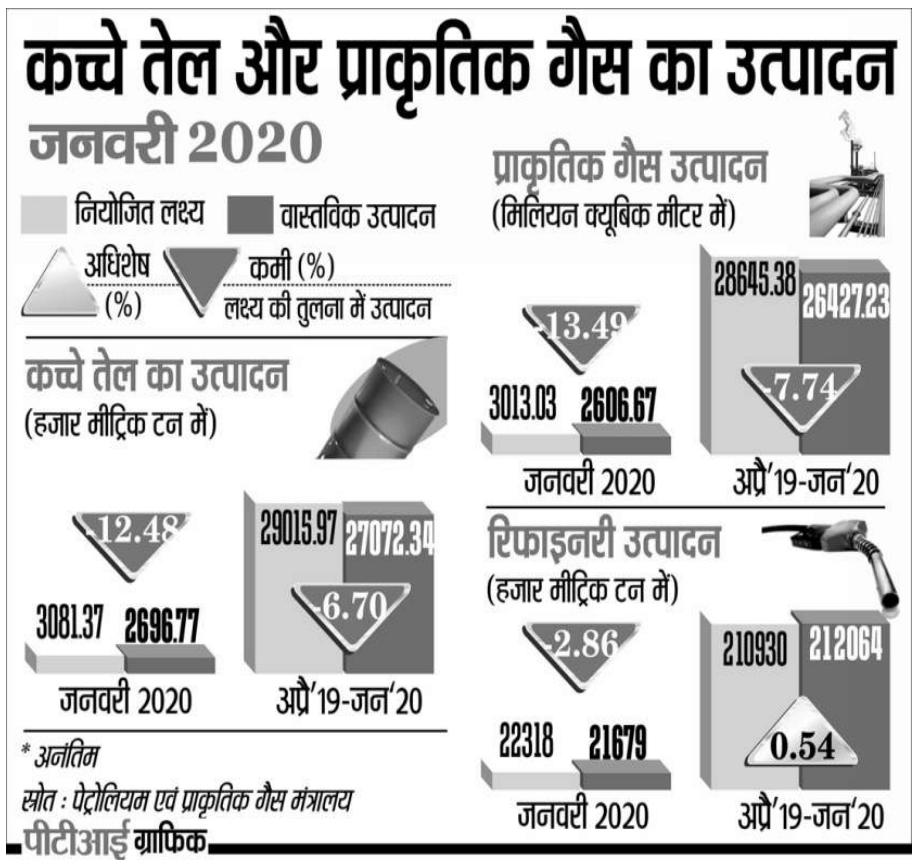

जैविक खाद्य उत्पादों की बढ़ रही मांग

भाषा
नई दिल्ली, 21 फरवरी

देश का जैविक खाद्य बाजार सालाना 17 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। दुनियाभर में स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण इसमें और अधिक तेजी से वृद्धि की संभावना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज यह बात कही। हरसिमरत ने यहां जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह खान-पान महोत्सव महिला उद्यमियों के लिए आयोजित किया गया है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी भी मौजूद थीं। यह खान-पान महोत्सव भारत के जैविक खाद्य बाजार की क्षमता अवधारणा पर आधारित है। इसका आयोजन दोनों मंत्रालयों ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया है। यह महोत्सव 21 से 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें 180 महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थानों ने प्रतिभाग किया है। इस मौके पर बादल ने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने साथ आकर जैविक खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को पंख देकर आसमान छूने का अवसर दिया है।

हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री

उन्होंने कहा कि यह महोत्सव देशभर में छह बार आयोजित किया जाएगा। इसे आने वाले सालों में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी बनाने का मकसद है। बादल ने कहा कि पूरी दुनिया स्वास्थ्यप्रद खाने के लिए जैविक खाने की तरफ देख रही है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आर्गेनिक और स्वास्थ्यप्रद खाने के लिए भारत एक पावर हाउस है। देश में सिक्किम, पहाड़ी राज्य और आदिवासी इलाके प्राकृतिक तौर पर आर्गेनिक खाने के लिए जाने जाते हैं। बादल ने कहा कि देश में जैविक खाद्य उत्पादों का कारोबार सालाना 17 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसमें आने वाले समय में और तेज वृद्धि होगी। इस महीने की शुरुआत में बादल ने कहा था कि अगले पांच साल में देश का जैविक खाद्य बाजार 75,000 करोड़ रुपये को छू जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के वास्ते मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रयासों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तेजी से बढ़ा है।

नीलामी प्रणाली का वित्त पोषण जारी रखे चाय बोर्ड

कलकत्ता चाय व्यापारी संगठन (सीटीटीए) ने शुक्रवार को कहा कि वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था नहीं होने तक चाय बोर्ड को देश में छह केंद्रों पर नीलामी प्रणाली को पैसे देना जारी रखना चाहिए। सीटीटीए के सचिव जे. कल्याणसुंदरम ने कहा कि मौजूदा समय में छह नीलामी केंद्रों में सालाना लगभग 60 करोड़ किलोग्राम चाय की खरीद-बिक्री की जाती है। कल्याणसुंदरम ने बताया कि ये केंद्र एनएसई डॉट आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जो पूरी तरह से चाय बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है। यदि चाय बोर्ड, नीलामी प्रणाली का वित्त पोषण बंद करने का फैसला करता है, तो चाय उद्योग के सामने अचानक से विकल्पहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

सीटीटीए कोलकाता केंद्र में नीलामी प्रणाली की देखरेख करता है। कल्याणसुंदरम ने कहा कि नीलामी के परिचालन का खर्च अभी चाय बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। वह लागत का एक हिस्सा वसूलने के लिए खरीदारों, दलालों और विक्रेताओं द्वारा बेची गई चाय के लिए दो पैसे प्रति किलोग्राम का शुल्क लेता है। उन्होंने कहा कि मैनुअल नीलामी प्रणाली में वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि एमजंक्शन द्वारा असम के जोरहाट में बनाए गए एकमात्र निजी प्लेटफॉर्म ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। *भाषा*

कृषि और फार्मा उत्पादों के लिए मुंबई में टर्मिनल

एजेंसियां
मुंबई, 21 फरवरी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीवीके एक संयुक्त उद्यम द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे ने शुक्रवार को कृषि और फार्मा उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक विशेष टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की। मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) ने कहा कि हवाई अड्डे पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े तापमान-नियंत्रित सुविधा केंद्र के रूप में प्रचारित इस 'एक्सपोर्ट कोल्ड जोन' में एक साथ 700 टन से ज्यादा का सामान रखा जा सकता है। इसकी संयुक्त वार्षिक क्षमता 5.25 लाख टन है। एमआईएएल ने कहा कि इस सुविधा केंद्र का परिचालन कार्गो प्रबंधन सेवा प्रदाता और एमआईएएल के कारोबारी साझेदार कार्गो सर्विस सेंटर द्वारा किया जाएगा।

एमआईएएल ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डा देश में फार्मा और कृषि उत्पादों की आवाजाही का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। पूरी तरह से स्वचालित बुनियादी ढांचा फार्मा और कृषि वस्तुओं की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करता है। यह 60 एयरलाइनों के जरिये 175 देशों में 500 से अधिक कार्गो गंतव्यों को जोड़ता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह एक्सपोर्ट कोल्ड जोन 12 ट्रक डॉक, डॉक-लेवलरों, विशाल प्रतिग्रहण और जांच क्षेत्र, स्वचालित वर्कस्टेशनों, एक्स-रे मशीनों, यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) भंडारण, यूएलडी ट्रांसफर और कोल्ड रूम के लिए बालमैट सिस्टम से लैस है। 6,000 वर्ग मीटर के परिचालन क्षेत्र में फैला यह सुविधा केंद्र 10 यूएलडी कार्यस्थलों और 172 यूएलडी स्टोरेज स्थलों से सुसज्जित है।

मुंबई हवाई अड्डा 'आईएटीए सीईवाई फार्मा' मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला और एशिया का तीसरा हवाई अड्डा है। यह हवाई परिवहन उद्योग को प्रशस्त करने वाली वैश्विक मान्यता होती है।

एपीडा ने बासमती के दो ब्रांडों पर लगाया प्रतिबंध

सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के आयातकों के दो निजी बासमती ब्रांड प्रतिबंधित

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 21 फरवरी

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के आयातकों के स्वामित्व वाले दो निजी बासमती चावल ब्रांडों - मोहसिन और आवाज को प्रतिबंधित कर दिया है। विदेशी आयातकों की भुगतान में चूक के कारण तत्काल प्रभाव से ऐसा किया गया है। दो साल पहले तक कई भारतीय निर्यातक ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन तथा खाड़ी और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों से ऑर्डर ले रहे थे। वे इन दोनों निजी ब्रांडों के तहत 1,121 किस्म वाले बासमती चावल की खेप भेज रहे थे।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी एशिया और ईरान में कई आयातकों ने भारतीय निर्यातकों के भुगतान में 20 करोड़ डॉलर की चूक की थी। यह और भी अधिक हो सकती है। पश्चिमी एशिया और ईरान में आयातकों ने रातों-रात अपना काम बंद कर दिया और गायब हो गए।

एपीडा ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत से निजी ब्रांडों - मोहसिन और आवाज के बासमती चावल निर्यात पर आयातकों द्वारा भुगतान न किए जाने के संबंध में एपीडा को निर्यातकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मोहसिन और आवाज ब्रांड को प्रतिबंधित करने फैसला किया गया है।

समय-समय पर की जाने वाली भुगतान चूक के कारण इन दोनों ब्रांडों पर तीन सालों से भारत सरकार की निगाह थी। किसी भी विवाद से बचने के लिए एपीडा ने भारतीय निर्यातकों को अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकारी एजेंसी ने इन दोनों दागी ब्रांडों के तहत बासमती चावल की खेप के लिए निर्यातकों को पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी नहीं करने की चेतावनी दी है। एपीडा ने एक परिपत्र में कहा है कि मोहसिन और आवाज ब्रांडों के तहत किसी भी देश को बासमती चावल निर्यात के लिए एपीडा द्वारा तत्काल प्रभाव से कोई आरसीएसी जारी नहीं किया जाएगा।

अप्रैल और दिसंबर 2019 की अवधि में भारत ने 3.1 अरब डॉलर मूल्य का 28.6 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार इस कारोबार को किसी भी रोक से मुक्त रखना चाहती थी इसलिए कार्रवाई करने में समय लग गया। लेकिन भुगतान चूक बढ़ती ही जा रही है।

हालांकि विदेशी चूककर्ताओं की हिस्सेदारी 10 फीसदी रह सकती है, लेकिन निर्यात मूल्य श्रृंखला में भारतीय निर्यातकों और अन्य लोगों को शेष हानि उठानी पड़ी है। हम नहीं चाहते थे कि भारतीय किसान, निर्यात मूल्य श्रृंखला में निर्यातक और अन्य लोगों को अंतहीन रूप से हानि हो। इसलिए हमने इन दोनों ब्रांडों को प्रतिबंधित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बासमती चावल निर्यात के मामले में भारत ने काफी इजाफा किया है। बासमती चावल निर्यात के संबंध में यूरोप में कीटनाशक तत्वों जैसी अन्य दिक्कतें हैं। लेकिन भारत ने इसके निर्यात में काफी उन्नति कर ली है।

- विदेशी आयातकों की भुगतान में चूक के कारण ऐसा किया गया
- पश्चिमी एशिया और ईरान में कई आयातकों ने भारतीय निर्यातकों के भुगतान में 20 करोड़ डॉलर की चूक की थी
- दो साल पहले तक कई भारतीय निर्यातक ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन तथा खाड़ी और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों से ऑर्डर ले रहे थे
- वे इन दोनों निजी ब्रांडों के तहत 1,121 किस्म वाले बासमती चावल की खेप भेज रहे थे

कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति में गिरावट

भाषा
नई दिल्ली, 21 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 40.56 करोड़ टन थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में कोल इंडिया की बिजली कंपनियों को कोयला आपूर्ति 2.9 प्रतिशत बढ़कर 4.32 करोड़ टन रही जो पिछले वित्त वर्ष की जनवरी में 4.2 करोड़ टन थी। कोल इंडिया की अनुषंगी सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने अप्रैल-जनवरी अवधि में 4.40 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में की गई 4.52 करोड़ टन कोयला आपूर्ति से 2.6 प्रतिशत कम है।

एक अधिकारी ने बारिश को कोयला क्षेत्र का दुश्मन बताते हुए कहा कि जुलाई के बाद मॉनसून के लंबी अवधि तक बने रहने से भी चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन घटा है। कोल इंडिया का अप्रैल-जनवरी अवधि में उत्पादन भी 3.9 प्रतिशत घटकर 45.15 करोड़ टन रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में कंपनी का कोयला उत्पादन 46.96 करोड़ टन था। हालांकि कोल इंडिया ने अगले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन 75 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल इंडिया का वित्त वर्ष 2023-24 तक कोयला उत्पादन एक अरब टन पहुंचाने का लक्ष्य है।

- कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही
- पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 40.56 करोड़ टन थी

नव निकाय के पांच साल

एक नीतिगत परामर्श निकाय के तौर पर आयोग ने काफी अच्छे काम किए हैं लेकिन इसमें कई खामियां भी हैं। खराब आर्थिक दौर से गुजर रहे देश को उबारने में उसे अहम भूमिका निभानी होगी

संजीव मुखर्जी

लाल किले के प्राचीर से अपना पहला भाषण देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले गठित योजना आयोग को खत्म करने और उसकी जगह नीति आयोग नाम से एक नई संस्था बनाने की घोषणा की थी। यहां पर नीति शब्द 'नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' का कूटनाम है।

नीति आयोग के गठन का औपचारिक फैसला 1 जनवरी 2015 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया था। मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि अफसरशाह अमिताभ कांत को इसका मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बनाया गया।

नीति-निर्माता शुरू से ही एकदम साफ थे कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग के पास फंड आवंटित करने की शक्तियां नहीं होंगी और यह सरकार के लिए महज थिंक-टैंक के तौर पर काम करेगा। इसके जरिये केंद्र एवं राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की धारणा को मजबूत बनाने की सोच भी रही है।

गठन के बाद के कुछ महीने तो आंतरिक व्यवस्था दुरुस्त करने में ही लग गए लेकिन इसे पटरी पर आने में अधिक देर नहीं लगी। आयोग की शासकीय परिषद की बैठक प्रधानमंत्री की अगुआई में हुई और उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में कई बहुमूल्य सुझाव सामने आए जिनमें केंद्र-प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस पैनल को सरकारी व्यय में होने वाले नुकसान पर काबू पाने के सुझाव देने को कहा गया।

नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद आयोग ने देश भर में डिजिटल मुहिम को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ सलाह-मशविरे के बाद उसने डिजिटल भुगतान परिदृश्य को लेकर कई अहम सुझाव दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले गठित योजना आयोग को खत्म करने और उसकी जगह नीति आयोग नाम से एक नई संस्था बनाने की घोषणा की थी

नीति आयोग ने नेहरू युग की विरासत कही जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लेने के लिए तीन-वर्षीय दृष्टिकोण पत्र भी तैयार किया था।

लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच यह बात साफ हो गई कि नीति आयोग केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर नीति-निर्माण को प्रभावित करने के मामले में योजना आयोग की धुंधली छाया ही रह गया है। वित्तीय रूप से भी कमजोर होने से आयोग के कामकाज में शुरू से ही रुकावट आती रही।

योजना आयोग के पूर्व सदस्य-सचिव एन सी सक्सेना कहते हैं कि एक संकल्पना के स्तर पर नीति आयोग बहुत ही अच्छा है लेकिन अपनी सोच को लागू कराने के स्तर पर यह निष्प्रभावी है। वह कहते हैं, 'नीति आयोग की संकल्पना सरकारी कार्यक्रमों के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता और वित्तीय बोझ के बगैर नीतिगत सुझाव देने वाले थिंकटैंक के तौर पर की गई है। लेकिन उसके सुझाए विचारों को लागू करने का सवाल आता है तो यह खेदजनक है।'

उनका कहना है कि जब सरकारी कार्यक्रमों के स्वतंत्र मूल्यांकन का वक्त आता है तो कई बार नीति आयोग के प्रमुख पूरी तरह सरकार-समर्थक नजर दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में भला उनके मातहत यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल्यांकन पूरी तरह स्वतंत्र एवं तार्किक ही होगा? सक्सेना कहते हैं, 'नीति आयोग ने संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर कुछ परिणाम रिपोर्ट पेश की हैं लेकिन उनमें गुणवत्ता की कमी नजर आती है। इनमें दी गई रैंकिंग किसी गिरावट या सुधार के असली कारण नहीं बताती है। इसके अलावा इन रिपोर्टों में दिए गए अधिकांश आंकड़े पुराने और अप्रचलित हो चुके हैं। कुल मिलाकर मैं नीति आयोग से बहुत खुश नहीं हूं।'

2018 के बजट में मिला प्रोत्साहन

नीति आयोग के गठन के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में उसकी अहमियत को स्वीकार किया गया। उस बजट में कई जगह आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में की गई छह बड़ी घोषणाओं में नीति आयोग की भूमिका रही थी।

किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए राज्यों के साथ चर्चा कर एक व्यवस्था बनाने से लेकर कृत्रिम मेधा (एआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का खाका तय करने तक हर बड़ी घोषणा में नीति आयोग नजर आ रहा था।

पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उठाया गया एक बड़ा कदम यह है कि आयोग गैर-वन क्षेत्रों में पैदा होने वाले बांस को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया गया है। 2018-19 के बजट में बांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। जेटली ने बजट में राष्ट्रीय बांस अभियान शुरू करने के साथ ही उसके लिए 1,290 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा था।

पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को वाजिब अधिकार देने के लिए राज्यों को भूमि पट्टा कानूनों में बदलाव के लिए भी कहा गया। वित्त मंत्री ने आयोग से एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने को कहा था जिसमें पट्टेदार किसानों को भी कर्ज लेने की इजाजत दी जा सके। यह व्यवस्था राज्यों के साथ परामर्श के बाद तैयार की जानी थी।

> नीति आयोग कृत्रिम मेधा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू करेगा। एआई के अनुप्रयोग के लिए शोध एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा

इसके अलावा आयोग ने बजट में उल्लिखित आयुष्मान भारत योजना का खाका तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल बीमा मुहैया कराएगी। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए नीति आयोग इस पर नए सिरे से गौर कर रहा है।

नीति आयोग कृत्रिम मेधा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू करेगा। एआई के अनुप्रयोग के लिए शोध एवं विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा आयोग एयर इंडिया समेत कई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश को सफल बनाने पर भी काम कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, सोने को एक परिसंपत्ति श्रेणी के तौर पर एक समग्र स्वर्ण नीति लाना और आसानी से स्वर्ण जमा खाता खोलने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन की कवायद भी नीति आयोग के ही दिमाग की उपज है।

नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि देश के अग्रणी थिंकटैंक के तौर पर आयोग सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ ई-वाहन और एआई जैसे नवाचारी क्षेत्रों में नीतिगत दिशा देने के लिए अधिकृत है। वह कहते हैं, 'पिछले पांच वर्षों में आयोग ने संपोषणीय विकास लक्ष्यों, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, नवाचार और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे क्षेत्रवार सूचकांकों के जरिये राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना जगाई है।'

मोदी 2.0 में समस्या

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती कुछ महीनों में केंद्र के साथ नीति आयोग के संबंधों में थोड़ा बदलाव दिखा है। प्रेक्षकों को लगता है कि आयोग कुछ मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही मुखर रहा है जिससे उसे कई बार केंद्रीय मंत्रियों की आलोचना भी झेलनी पड़ी है।

गत वर्ष अगस्त में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहते हुए आयोग की खिल्ली उड़ाई थी कि उसे वाहन प्रौद्योगिकी के बारे में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से उनके मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है। खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाने वाले गडकरी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आईसीई इंजनों से लैस वाहनों का पंजीकरण रोकने संबंधी नीति आयोग के रुख पर यह टिप्पणी की थी।

प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की मुहिम में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा करने वाली फेम योजना के पीछे भी नीति आयोग की ही भूमिका रही है।

सूत्र बताते हैं कि आयोग के वरिष्ठ सदस्यों और प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों के बीच हुई एक बैठक में तनातनी की स्थिति बन गई थी। दरअसल आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने की समयसीमा पर सख्ती बरत रहा था। आयोग आईसीई इंजनों वाले वाहनों की बिक्री पर चरणबद्ध रोक लगाने के भी पक्ष में था।

बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने आईसीई इंजनों का पंजीकरण रोकने की किसी भी पहल पर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के एक रोडमैप पर चलना जारी रखेंगी।

इसके कुछ दिनों बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सेमिनार में कहा कि कई मुद्दों पर नीति आयोग की राय हमेशा सरकार का ही रुख नहीं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह लगातार नए समाधान लेकर आने वाला एक स्वतंत्र थिंकटैंक है। वह आरएसएस से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ द्वारा नौकरियां खत्म करने और सरकारी संपत्तियों की बिक्री के लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।

इसके कुछ हफ्ते पहले नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच इस बात को लेकर खींचतान हो गई थी कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम मेधा केंद्र पर मालिकाना हक किसका होगा? आयोग ने एआई नेटवर्क बनाने के लिए तीन वर्षों के भीतर 7,500 करोड़ रुपये की मांग की थी जबकि आईटी मंत्रालय ने इस पर 470-480 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था।

मंत्रालय ने नागरिकों के लिए एआई के इस्तेमाल का आकलन करने के लिए 2018 में चार पैनल गठित किए थे। इन पैनल को डेटा प्लेटफॉर्म का गठन, कौशल विकास, शोध एवं विकास और कानूनी, नियामकीय, नैतिक एवं साइबर-सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को परखना था। इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

नीति आयोग भी गत जून में कृत्रिम मेधा पर राष्ट्रीय रणनीति विषय पर एक विमर्श-पत्र लेकर आया था।

वैसे एआई जैसे नई प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के दायरे में आती है लेकिन नीति आयोग ने इस मसले पर कई चर्चाएं की हैं। आयोग की तरफ से जून में पेश विमर्श-पत्र की इस बात के लिए प्रशंसा हुई थी कि इसमें एआई के जरिये हल किए जा सकने वाले मसलों का बढ़िया खाका पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक क्रियान्वयन का कोई व्यापक रोडमैप नहीं दिया गया था।

इसके अलावा नीति आयोग का कई अन्य बिंदुओं पर भी सरकार से अलग रुख रहा है। यहां तक कि खुद आयोग के भीतर भी कई महत्त्वपूर्ण मसलों पर विरोधाभासी विचार रहे हैं।

नैसर्गिक खेती को सरकारी प्रोत्साहन इसकी एक बानगी है। सुभाष पालेकर द्वारा विकसित शून्य-बजट नैसर्गिक खेती तकनीक के जरिये सरकार इस खेती तकनीक को बढ़ावा देना चाहती है। नीति आयोग के प्रमुख राजीव कुमार इस तकनीक के घोषित समर्थक हैं लेकिन आयोग के वरिष्ठ सदस्य रमेश चंद को लगता है कि नैसर्गिक खेती खाद्य उत्पादों में रसायनों से बचाव का एकमात्र समाधान नहीं है।

हालांकि तमाम जानकारों का कहना है कि एक स्वतंत्र विचार-समूह होने से नीति आयोग से यह अपेक्षित है कि वह सरकार के रुख से अलग राय रखने वाले मुद्दों पर अपने विचार रखे। लेकिन अगर यह मतभेद टकराहट में तब्दील हो जाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं।

कुछ रिपोर्टों ने कहा कि उद्योग की हालत सुधारने के लिए उपायों पर आयोग के सख्त रुख के चलते ही सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं।

सवाल यह है कि ये तमाम कदम व्याख्या के लिए कितने सही हैं? पहला, पिछले पांच वर्षों में नीति आयोग को आरएसएस के विभिन्न अनुषंगी संगठनों से होने वाली तमाम आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन कहते हैं, 'मेरे हिसाब से इधर-उधर किए गए तमाम बदलावों के बावजूद नीति आयोग वह भूमिका नहीं निभा रहा है जिसके लिए उसका गठन हुआ था। न तो वह राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती दे रहा है और न ही वह आर्थिक मसलों पर समुचित नीतिगत सलाह ही दे पा रहा है। ऐसा लगता है कि आयोग बाहरी सलाहकारों पर कुछ ज्यादा ही आश्रित हो गया है।'

> नीति आयोग को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उस मुकाम से आगे बढ़ना होगा जहां वह पहले पहुंच चुका है। अगर वह मौजूदा मुश्किल आर्थिक परिवेश में ऐसा कर पाता है तो भारत के वृद्धि पथ पर गहरा असर डाल सकता है

महाजन बीपीसीएल के विनिवेश का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नीति आयोग ने लगातार इस विनिवेश प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन इस मसले के सभी घटकों पर उसने शायद ही ध्यान दिया है। महाजन कहते हैं, 'मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में किसी मुद्दे को परखने के बाद ही उस पर अंतिम सलाह देनी चाहिए।'

बहरहाल नीति आयोग को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उस मुकाम से आगे बढ़ना होगा जहां वह पहले पहुंच चुका है। अगर वह मौजूदा मुश्किल आर्थिक परिवेश में ऐसा कर पाता है तो भारत के वृद्धि पथ पर गहरा असर डाल सकता है।

पानगड़िया की विदाई आयोग को झटका

वर्ष 2017 के मध्य में नीति आयोग को पहला बड़ा झटका लगा था जब उसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना अधूरा शैक्षणिक कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस इस्तीफे में साजिश देखने वालों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ रिश्तों में आई नरमी ही इसकी असल वजह थी। कहा गया कि संघ परिवार के कुछ घटकों को पानगड़िया अधिक पसंद नहीं थे। उनकी विदेशी पृष्ठभूमि के अलावा नीति आयोग को दी गई सीमित शक्तियां भी संघ परिवार को रास नहीं आ रही थी।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि पानगड़िया नवंबर 2016 में लागू की गई नोटबंदी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस बारे में भले ही उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला था लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को यह नागवार गुजरा था। बहरहाल, पानगड़िया के इस्तीफे के कुछ दिनों के भीतर ही सरकार ने वित्त मंत्रालय के पूर्व आर्थिक सलाहकार और चर्चित अर्थशास्त्री राजीव कुमार को नीति आयोग का अगला उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उस समय यह कहा गया कि राजीव अरविंद पानगड़िया के शायद माकूल विकल्प हैं। इससे विदेश में उच्च शिक्षा लेकर लौटने वाले अर्थशास्त्रियों के घरेलू आर्थिक परिवेश को ठीक से नहीं समझ पाने को लेकर जारी चर्चा पर भी लगाम लग गई।

इस घटना के कुछ महीनों बाद नीति आयोग के काफी चर्चित सदस्य विवेक देवरॉय को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बना दिया गया। इस सलाहकार परिषद का कार्यालय नीति आयोग में ही है।

राजीव चाहते हैं कि नीति आयोग को सहकारी संघवाद के एक असरदार उपकरण के तौर पर देखा जाए। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा, 'नीति आयोग केंद्र सरकार में नए विचार और रूपांतरकारी पहल ले आने के प्रयास करेगा। हम चाहेंगे कि आयोग को आने वाले वर्षों में सहकारी संघवाद के एक प्रभावी साधन के तौर पर देखा जाए।'

नई दिल्ली | 22 फरवरी 2020 शनिवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

आईपीएल में विज्ञापन के लिए ब्रांड में लगी होड़

इस टूर्नामेंट के साथ दर्शकों के जुड़ाव को देखते हुए स्टार स्पोर्ट्स बना ब्रांड की पसंद

टी ई नरसिम्हन

स्टार स्पोर्ट्स ने अगले महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टूर्नामेंट के 13वें संस्करण के लिए अपने प्रसारण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही 55 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विज्ञापन देने की योजना लगभग हरेक ब्रांड ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 13 ब्रांड पहले ही विज्ञापन करार कर चुके हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल विज्ञापन की दरें भी 10-15 फीसदी बढ़ा दी गई हैं।

लेकिन ब्रांड और मार्केटिंग विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि भारी आर्थिक सुस्ती के बीच 6.8 अरब डॉलर मूल्य (डफ ऐंड फेल्प्स, आईपीएल 2019) वाले इस टूर्नामेंट की कीमत कहीं बहुत अधिक तो नहीं लगाई गई है।

पहले से ही आईपीएल विज्ञापन करार कर चुके ब्रांड पिछले साल भी आईपीएल-स्टार गठजोड़ का हिस्सा थे। इन ब्रांड में विवो, कोका कोला इंडिया, एमेजॉन, नेस्ले, फोनपे, ड्रीम11 और मारुति सुजूकी शामिल हैं। ऐसी खबरें हैं कि स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल-2020 में राजस्व संग्रह का लक्ष्य 2019 की तुलना में 40 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आईपीएल मैचों के दौरान विज्ञापन देने की लागत बढ़ेगी और लीग के साथ नए ब्रांडों को भी जोड़ा जाएगा।

विज्ञापन एवं मीडिया व्यवसायी और मोगे मीडिया के संस्थापक संदीप गोयल का कहना है कि टूर्नामेंट ने अपनी प्रेरणा को हासिल किया है और उस वजह से इसकी दरें काफी अधिक हैं। वह कहते हैं, 'आईपीएल नई पीढ़ी को लक्षित ब्रांडों के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच है। यह साल का वह समय होता है जब दर्शक संख्या चरम पर होती है। ब्रांड आईपीएल के दौरान विज्ञापन स्लॉट खरीदने के लिए अपना बजट बचाकर रखते हैं।'

वीवो इंडिया के निदेशक (ब्रांड रणनीति) निपुण मारिया के मुताबिक आईपीएल जैसे टूर्नामेंट से जुड़ाव के काफी फायदे भी हैं। वीवो आईपीएल में मैदान पर टाइटल प्रायोजक और स्टार स्पोर्ट्स के प्रसारण साझेदार भी है। निपुण कहते हैं कि आईपीएल प्लेटफॉर्म किसी भी ब्रांड के लिए अपने ग्राहकों के साथ जुड़ाव के तमाम मंच मुहैया कराता है। वह कहते हैं, 'हमने 2016 से ही अपने ब्रांड को निर्मित करने के लिए आईपीएल को एक मौके के तौर पर देखा और इस साथ ने जागरूकता जगाने एवं अपने ग्राहकों से सार्थक जुड़ाव कायम करने में मदद की है।'

हालांकि कुछ लोग इससे इत्तफाक नहीं भी रखते हैं। पहले इस टूर्नामेंट से जुड़े रह चुके एक बड़े वैश्विक ब्रांड ने इस बार आईपीएल से अलग रहने से दूर रहने का फैसला किया है। इस कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि विज्ञापन एवं प्रायोजन की दरें अयथार्थवादी तरीके से ऊंची हैं जिससे यह टूर्नामेंट साल भर में ही तमाम ब्रांडों की पहुंच से दूर हो गया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति में अधिकांश कंपनियों के लिए अपने बजट को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

गोयल का कहना है कि भारतीय ब्रांडों के लिए आईपीएल उसी तरह का खेल आयोजन है जैसा अमेरिकी ब्रांडों के लिए सुपर बाउल टूर्नामेंट है। सुपर बाउल के साथ विज्ञापन की दरें बढ़ने के बावजूद अमेरिकी ब्रांड इससे जुड़ने को हमेशा तरजीह देते हैं। ब्रांड फाइनैंस के निदेशक सेवियो डिसूजा के मुताबिक नए उत्पादों एवं विज्ञापन अभियानों की लॉन्चिंग की योजना आईपीएल के आसपास ही रखी जाती है। इसकी वजह यह है कि यह टी-20 क्रिकेट लीग अब भी उम्मीदों पर खरी उतरती है। डिसूजा कहते हैं, 'आईपीएल का दर्जा क्रिकेट जगत में कुछ वैसा ही हो गया है जैसा फुटबॉल में ला लीगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का है।'

आईपीएल 2019 के बारे में जारी ब्रांड फाइनैंस की रिपोर्ट कहती है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान करीब 330 अरब मिनट का प्रसारण हुआ और 30 करोड़ लोगों ने स्ट्रीमिंग सेवाओं पर भी इसे देखा था। इन आंकड़ों से परे आईपीएल के साथ दर्शकों का जुड़ाव, सघनता और लगातार भागीदारी ने इसे ऐसा रूप दे दिया है जिससे हर ब्रांड जुड़ना पसंद करता है। आईपीएल के साथ अपना करार जारी रखने जा रहे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे के एक प्रवक्ता के मुताबिक, इस टूर्नामेंट ने आम लोगों के बीच ब्रांड को लेकर जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है और अब उपभोक्ताओं का बड़ा तबका ब्रांड को लेकर रुचि दिखाने लगा है। फोनपे को उम्मीद है कि 2020 में भी आईपीएल के साथ विज्ञापन करार जारी रहने से उसे डिजिटल लेनदेन के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस साझेदारी से फोनपे को अपनी सेवाओं एवं फीचर को लेकर संदेश पहुंचाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। दर्शक संख्या और ब्रांड भागीदारी में आए बड़ी उछाल के बावजूद आईपीएल को दूसरे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मुकाबले में पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। ब्रांड फाइनैंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल की शीर्ष पांच टीमों का संयुक्त रूप से ब्रांड मूल्य 32.1 करोड़ डॉलर है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा की शीर्ष पांच टीमों के समेकित ब्रांड मूल्य (क्रमश: 6.5 अरब डॉलर और 4.2 अरब डॉलर) से बहुत अधिक है।

टूर्नामेंट के प्रसारक एवं फ्रैंचाइजी टीमों के मालिक इस फासले को कम करने के लिए आईपीएल ब्रांड के आर्थिक दोहन का हरसंभव मौका भुनाने में लगे हैं। वर्ष 2020 में आईपीएल 2019 की तुलना में करीब एक हफ्ते अधिक समय तक चलेगा। ऐसे में आयोजकों को उम्मीद है कि अधिक वक्त मिलने से अधिक कंपनियां विज्ञापन करने के लिए प्रेरित होंगी।

स्टार स्पोर्ट्स अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर भी अधिक विज्ञापन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। गोयल का मानना है कि स्टार अपनी डिजिटल रणनीति के फायदे भुनाने में लगा हुआ है। पहले ब्रांड अपने विज्ञापन बजट का 90 फीसदी हिस्सा टीवी प्रसारण पर देती रही हैं और डिजिटल विज्ञापन महज 10 फीसदी ही रहता है। लेकिन अब यह राजस्व स्टार और हॉटस्टार के बीच 75:25 और 67:33 के अनुपातिक दायरे तक पहुंच चुका है। इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत रेखांकित होती है।

आईपीएल का रोमांच

- इस संस्करण का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा
- टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा
- टूर्नामेंट 57 दिनों तक चलेगा जो 2019 संस्करण से एक हफ्ते अधिक है

छोटे शहरों में टिकटॉक का बढ़ता दायरा

टी ई नरसिम्हन

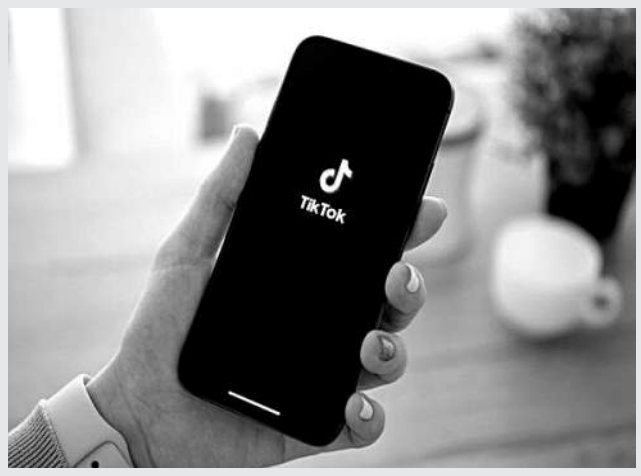

- 2019 में टिकटॉक पर बिताए गए समय में वैश्विक स्तर पर 210 फीसदी की तेजी आई
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टिकटॉक, हेलो का बढ़ा चलन
- आईआईएम इंदौर ने मार्केटिंग तथा बिजनेस मैनेजमेंट पर पाठ्यसामग्री लाने के लिए टिकटॉक से साझेदारी की
- केरल तथा उत्तराखंड पुलिस लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कर रही इसका इस्तेमाल

जिस समय भारतीय बाजार में अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों का प्रभुत्व बना हुआ है ऐसे में टिकटॉक और हेलो के मालिकाना हक वाली चीन की कंपनी बाइटडांस भारतीय बाजार, विशेषकर महानगरों से बाहर छोटे शहरों में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। छोटे वीडियो बनाने वाली कंपनी के दोनों ऐप 'ऐप एनी' द्वारा जारी स्टेट ऑफ दी मोबाइल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2019 के लिए सोशल ऐप के मामले में शीर्ष दो स्थानों पर रहे हैं। भारत कंपनी के लिए चीन से बाहर सबसे बड़ा बाजार है।

एक तरफ हेलो स्थानीय भाषाओं में अपना प्रसार कर रहा है तो वहीं टिकटॉक छोटे तथा मझोले शहरों पर नजर बनाए हुए है। बाइटडांस के प्रवक्ता ने कहा कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के चलते इन ऐप की लोकप्रियता बढ़ी है। ऐप एनी की रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक पश्चिमी देशों में प्रसार के लिए भी कदम उठा रही है और इसने कनाडा की ऐप सूची में पहला स्थान तथा अमेरिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर, साल 2019 में टिकटॉक पर बिताए जाने वाले समय में बढ़ोतरी हुई है और भारत में इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'भारत तथा अमेरिका के उदाहरणों के देखते हुए यह माना जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर सोशल ऐप की मांग बढ़ी है क्योंकि उपभोक्ता फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया ऐप की तरह ही स्थानीय ऐप की तलाश करते हैं।'

भारत में टिकटॉक तथा हेलो काफी सही रणनीति के साथ आगे बढ़ी हैं। बाजार में देरी से प्रवेश करने के बजाए दोनों ने उपयोगकर्ताओं के मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप के साथ पूरा एक नेटवर्क विकसित किया। कंपनी का दावा है कि भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

बाइटडांस के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लोकप्रिय सामग्री निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों और लोकप्रिय हस्तियों ने टिकटॉक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे सामग्री के लिहाज से बहुआयामी प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की।

> हेलो तथा टिकटॉक, ऐप पर पहली बार आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आसान इंटरफेस उपलब्ध है

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के ऐप निर्माता अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले अलग तरीके से काम करते हैं। चीनी निर्माताओं के मंच वैश्विक मानकों के अनुरूप लोकप्रिय ढांचा बनाने के बजाए इसमें स्थानीय तत्त्वों को शामिल करते हैं। बाइटडांस के लिए भारत काफी अहम है और यह चीन के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी ने भारतीय बाजार की जरूरत तथा सीमाओं को समझने में काफी निवेश किया है।

हेलो तथा टिकटॉक, दोनों ऐप पर पहली बार आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए काफी आसान इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है। शुरुआती दिनों में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने की चुनौती थी क्योंकि इस पर कई कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। कंपनी ने इस आरोपों को नकारने के बजाए खामियों को दूर करने पर काम किया। इससे ऐप संबंधी विवाद समाप्त हुए और कारोबार में वापसी की। रिपोर्ट का कहना है कि टिकटॉक सोशल नेटवर्किंग साइट होने के साथ साथ मनोरंजन का स्रोत (विशेषकर 15-24 आयु वर्ग के वयस्कों के लिए) भी है। भारत में इसका इस्तेमाल एक शैक्षणिक मंच, सरकारी संदेश पहुंचाने, पुलिस तथा नागरिकों के बीच संवाद करने आदि के तौर पर भी किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए, आईआईएम इंदौर ने मार्केटिंग तथा बिजनेस मैनेजमेंट पर पाठ्यसामग्री लाने के लिए टिकटॉक से साझेदारी की है। वहीं, केरल तथा उत्तराखंड पुलिस लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहीं कई तकनीकी कंपनियां भी अपनी सामग्री टिकटॉक पर उपलब्ध करा रही हैं।

विविध कार्यों को अंजाम देने की क्षमता तथा कई भाषाओं में उपलब्ध यह प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग एवं एनालिटिक्स फर्म रेज कम्युनिकेशंस के निदेशक कार्तिक कुमार कहते हैं कि उपयोग करने में आसानी की विशेषता के चलते टिकटॉक की लोकप्रियता बढ़ी है। वह कहते हैं, 'कोई भी व्यक्ति किसी जटिल या भारी-भरकम उपकरण के बजाए आसानी से अपने मोबाइल से वीडियो बना सकता है।' विशेषज्ञ बताते हैं कि टिकटॉक ने बाइटडांस की 'भारत रणनीति' में मदद की है। इसका लक्ष्य छोटे शहरों के इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जिनमें से अधिकांश ने हाल ही में स्मार्टफोन तथा इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया है। कंपनी डीलर, सामग्री प्रदाता और रिटेलर जैसे सभी हितधारकों के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है कि टिकटॉक ऐप मोबाइल में पहले से ही उपलब्ध हो और सामग्री को अधिक रोचक बनाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसकी ओर आकर्षित किया जा सके।

लंदन में पैठ बना रही ओला

टी ई नरसिम्हन

उबर को लंदन में कारोबार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा

भारत की शोरगुल तथा भीड़भाड़ भरी सड़कें और छूट पर निगाह लगाए रखने वाली सवारियों के हिसाब से बनाई गई कंपनी ओला लंदन के राइड-हेलिंग कारोबार में किस तरह सेंध लगा रही है? खासकर जब इसी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी उबर अपने पैर जमाने के लिए जद्दोजहद कर रही हो। बेंगलूरु स्थित राइड हेलिंग कंपनी ओला की रणनीति में इसका जवाब छुपा है। हाल में लंदन में कारोबार शुरू करने वाली ओला ने अपना ब्रांड नाम बरकरार रखा है और विज्ञापनों में कंपनी भारत के लिए विकसित किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में बता रही है। उदाहरण के लिए, सफर शुरू करने से पहले ओटीपी साझा करने जैसी द्वि-स्तरीय सत्यापन प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि वे उसी कैब में सफर कर रहे हैं जिसे उन्होंने बुक किया है। ओला के सीओओ तथा सीएमओ (ग्लोबल) अरुण श्रीनिवास कहते हैं, 'इस बाजार में ग्राहक तीन मुख्य चीजें देखता है, सुरक्षा तथा आराम, साफ कार और अच्छी गुणवत्ता वाले वाहन चालक।' वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की यही मांग रहती है और ओला इन्हें पूरा करने में लगी है।

कंपनी की रणनीति में सुरक्षा अहम भूमिका में है और कंपनी एआई तकनीक आधारित उपाय 'गार्जियन' लेकर आ रही है। यह वाहन की अनियमित गतिविधियों की स्वयं पहचान कर लेता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि ऐप द्वारा जारी 'स्टार्ट कोड' की मदद से ग्राहक तथा चालक एक दूसरे का आसानी से मेल कर लेते हैं। ऐप में पैनिक बटन भी है जो यात्रियों तथा चालकों, दोनों के लिए 24 घंटे आवाज आधारित सहायता मंच तक पहुंच प्रदान करता है। कारोबार के लिहाज से लंदन में ओला की प्रतिस्पर्धी कंपनियों में उबर के अलावा बोल्ट तथा केप्टन शामिल हैं। हरीश बिजूर कंसल्ट्स के संस्थापक हरीश बिजूर कहते हैं, 'ओला लंदन में एक खाली जगह को भर रही है। वहां उबर काफी असुविधाजनक है। इस हिसाब से ओला को बेहतर कारोबार के लिए उबर से काफी सीखने की जरूरत है।' सॉफ्टबैंक की दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी है और दोनों भारतीय सड़कों पर एक दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। हालांकि ओला फिलहाल उबर के मुकाबले ज्यादा भारतीय शहरों में मौजूद है लेकिन आने वाले महीनों में उबर कई दूसरे शहरों में कारोबार शुरू करने की योजना बना रही है।

बिजूर मानते हैं कि ओला को अपने चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिष्टाचार को भी शामिल करना चाहिए और लंदन की अधिकांश टैक्सी सेवा प्रदाता इस दिशा में बेहतर कार्य नहीं कर रही हैं। साथ ही, युवा वाहन चालकों को कार्यप्रणाली में शामिल करने के लिए भी यह जरूरी है।

लंदन में परिचालन शुरू करने के बाद ओला ब्रिटेन के कुल 28 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और श्रीनिवास का दावा है कि ऐप को डाउनलोड करने की संख्या छह अंकों को पार कर गई है। ओला पहले सप्ताह में खाता खोलने पर 25 यूरो का राइड क्रेडिट भी दे रही है। शुरुआती ऑफर के तौर पर ओला से जुड़ने वाले वाहन चालकों को पहले छह सप्ताह तक उनकी कुल आय का शत प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेंगे। श्रीनिवास कहते हैं, 'एक साल के भीतर ओला बाजार में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ जाएगी।' कंपनी का कहना है कि वाहन चालकों, यात्री सुरक्षा तथा स्थानीय प्राधिकरणों एवं नियामकों के साथ साझा संवाद रणनीति के साथ आगे बढ़ने से लंदन के बाजार में पैठ बनाने में आसानी होगी।

ओला के प्लेटफॉर्म पर 25,000 से अधिक वाहन चालक पंजीकृत हो चुके हैं जो 'किराए पर निजी वाहन चलाने की अनुमति वाले लाइसेंस' धारकों की कुल संख्या का करीब आधा है। चालकों को लुभाने के लिए कंपनी छह महीने तक चालकों से कोई कमीशन नहीं लेगी और इसके बाद बाजार में प्रचलित कमीशन दर ही ली जाएंगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओला ने ब्रिटेन की जोखिम, सुरक्षा प्रबंधन तथा चालक प्रशिक्षण कंपनी ड्राइव टेक के साथ साझेदारी की है जिससे ओला से जुड़े वाहन चालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा, पीयरसन के साथ साझेदारी करके ओला यह सुनिश्चित कर रही है कि इससे जुड़े चालक यात्रियों के साथ स्पष्ट तथा सौम्यता के साथ व्यवहार करें। लंदन में कारोबार कंपनी की वैश्विक विस्तार रणनीति का हिस्सा है। ओला ने फरवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया। इसके बाद अगस्त 2018 में ब्रिटेन तथा नवंबर 2018 में न्यूजीलैंड में परिचालन शुरू किया।

ट्रंप यात्रा के लिए तैयार हुआ भारत

दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौतों पर ट्रंप दे रहे मिली-जुली प्रतिक्रिया, भारत भव्य स्वागत को तैयार

एजेंसियां

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सोमवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध और मजबूत होंगे।

भारत तथा अमेरिका राजनीतिक एवं सुरक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोगी हैं लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार शुल्क चर्चा का विषय बना रहा। पिछले कुछ महीनों से दोनों देश कारोबारी समझौते के लिए गहन बातचीत में लगे थे लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह अभी काफी मुश्किल लग रही है।

अमेरिका भारत के विशाल पॉल्ट्री तथा डेयरी बाजार में पहुंच बनाना चाहता है। हालांकि अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि स्टेंट जैसे चिकित्सकीय उपकरणों की कीमतों पर भारत का नियंत्रण तथा डेटा स्टोरेज के कठोर स्थानीय नियमों से कारोबार करने की लागत बढ़ जाएगी।

दूसरी ओर, भारत सरकार ने फार्मास्युटिकल तथा फार्म उत्पादों की अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच के साथ ही व्यापार रियायतों की बहाली की मांग की है, जिन्हें ट्रंप सरकार ने 2019 में वापस ले लिया था। इसके अलावा, भारत का कहना है कि अमेरिका को भारत के साथ चीन के साथ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से पांच गुना बड़ी है।

लास वेगास में हुए एक कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत के साथ कारोबारी समझौते को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'हम भारत जा रहे हैं और हम वहां एक शानदार समझौता कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इसमें थोड़ी देरी कर दें और इसे चुनाव के बाद पूरा करें।' अहमदाबाद में होने वाले ट्रंप के रोडशो में हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है और इस कार्यक्रम के लिए चुने गए सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता एक लाख से अधिक है।

विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा, '24 फरवरी को उनके हवाई अड्डे पर आते ही पूरे शिष्टमंडल को भारत की विविधता में एकता जैसे संदेश के साथ भारतीय मेहमाननवाजी की

- अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने भारत से होने वाले कारोबारी समझौतों को चुनाव बाद करने का दिया संकेत
- हालांकि कुछ चुनिंदा विषयों पर समझौतों की है उम्मीद
- उच्चस्तरीय शिष्टमंडल में ट्रंप की बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनेर और शीर्ष अमेरिकी अधिकारी होंगे शामिल

जाएगी।' उन्होंने बताया कि वहां हजारों आम लोगों के साथ देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार भी होंगे जो इंडिया रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस उच्चस्तरीय शिष्टमंडल में उनकी बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनेर तथा शीर्ष अमेरिकी अधिकारी शामिल होंगे।

कारोबारी सौदे की उम्मीद

सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक ऐंड इंटरनैशनल स्टडीज में भारतीय मामलों के विशेषज्ञ रिचर्ड एम. रॉशो का कहना है कि दोनों देशों के बीच बड़े कारोबारी समझौते के बजाय कुछ चुनिंदा विषयों पर समझौतों की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा, 'कई ऐसे विषय हैं जिन्हें भारत बातचीत के लिए टेबल पर रख सकता है और इनसे सरकारों के घरेलू मामलों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।'

उन्होंने बताया कि इसके तहत हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क में और कटौती की जा सकती है और ट्रंप पहले भी कई बार इस विषय पर बोल चुके हैं। इस बात की भी उम्मीद है कि दोनों देश लॉकहीड मार्टिन से करीब 2.6 अरब डॉलर कीमत की 24 सीहॉक नौसैनिक हेलीकॉप्टर और छह अपाचे लडाकू हेलीकॉप्टरों के खरीद सौदे की भी घोषणा कर सकते हैं।

पिछले 15 वर्षों में 18 अरब डॉलर से ज्यादा की बिक्री के साथ अमेरिका भारत का शीर्ष सैन्य सामान आपूर्तिकर्ता देश है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप तथा मोदी के बीच व्यापार, 5जी, दूरसंचार, आतंकवाद पर रोक, ऊर्जा सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, और भारत-प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

अमेरिका की ऊर्जा कंपनी वेस्टिंगहाउस को भी न्यूलियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ छह न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए नया समझौता होने की उम्मीद है।

साबरमती दौरे पर संशय

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि फिलहाल व्हाइट हाउस को यह फैसला करना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 24 फरवरी को शहर के एक दिवसीय दौरे के दौरान साबरमती आश्रम जाएंगे या नहीं। रूपाणी का यह बयान बीते दो दिनों से लगाई जा रही उन अटकलों के बाद आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम का दौरा नहीं करेंगे। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी का गहरा जुड़ाव रहा था।

पूर्व में यह घोषणा की गई थी कि 24 फरवरी को यहां पहुंचने पर ट्रंप साबरमती आश्रम जाएंगे और वहां करीब 30 मिनट तक रहेंगे। रूपाणी ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वह वाशिंगटन से सीधे अहमदाबाद आएंगे।

इस बीच, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि मोटेरा के नव निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में 24 फरवरी को 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करना नहीं है। एसोसिएशन बाद में इस स्टेडियम का उद्घाटन करेगा।

दूसरी ओर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान सभी अहम अवसरों के लिए एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रंग-बिरंगे फूलों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया, 'सजाने के लिए मौसमी पौधों, ट्यूलिप और कई रंगों वाले संकर डहेलिया की व्यवस्था की है, जिन्हें हैदराबाद हाउस में भी लगाया जायेगा।' हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी।

गुजरात के नव निर्मित स्टेडियम में होगा 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम का आयोजन

बिज़नेस स्टैंडर्ड- सीमा नाज़रेथ अवार्ड

आसान पत्रकारिता के फेर से बचे मीडिया: रवीश

रवीश कुमार ने कहा कि आर्थिक मुद्दे सामाजिक मुद्दों की तरह हैं अहम

बीएस संवाददाता

फर्जी और मनगढ़ंत सूचनाओं की बौछार तथा टिकटॉक शैली वाली फौरी खबरों के दौर में पत्रकारिता बड़े संकट का सामना कर रही है। इस पर चिंता जताते हुए मैगसायसाय पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि संकट संस्थागत स्तर पर भी है और व्यक्तिगत स्तर पर भी। इसीलिए मीडिया खुद चुने कि उसे तालाब में बंधकर 'आसान' पत्रकारिता करनी है या खबरों के समंदर में उतरना है।

प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2019 के बिज़नेस स्टैंडर्ड-सीमा नाज़रेथ अवार्ड समारोह में रवीश ने कहा, 'इस वक्त वह दौर है, जिसमें हम सूचना नहीं कथ्य चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थाएं, खास तौर पर टेलिविजन मीडिया वह भरोसा कायम नहीं रख पाया है, जो लोगों ने उसमें दिखाया था। लेकिन इस पेशे से जुड़े कुछ लोग खुद अपने दायरे बढ़ाने में जुटे हैं।

एनडीटीवी इंडिया के प्रबंध निदेशक रवीश ने कहा, 'हमने अपने तालाब चुन लिए हैं और हम समुद्र की यात्रा नहीं करना चाहते।' लेकिन उन्होंने कहा कि असली पत्रकारिता को कितना भी 'उबाऊ' बताया जाए, पत्रकार को उसी पर कायम रहना चाहिए क्योंकि मीडिया का भविष्य उसी से बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी समय लोगों को सशक्त बनाने वाला मीडिया अब उसकी ताकत छीन रहा है।

कारोबारी पत्रकारिता को बेहद अहम बताते हुए रवीश ने कहा कि कारोबारी मुद्दों की समझ बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'पत्रकार के तौर पर अगर आप अर्थव्यवस्था को और उससे जुड़ी दूसरी बातों को नहीं समझते हैं तो आप देश से बात नहीं कर सकते।' उनका कहना था कि आज के जमाने में आर्थिक मुद्दे उतने ही अहम हैं, जितने सामाजिक मुद्दे और उन्हें जनता के सामने ठीक तरीके से पेश करना जरूरी है।

इससे पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड के युवा पत्रकारों शुभायन चक्रवर्ती और वीरेश्वर तोमर को सम्मानित किया गया। शुभायन को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के पेचीदा मुद्दों की बेहतरीन समझ के लिए और सरल भाषा में उन्हें पेश करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड बिज़नेस स्टैंडर्ड की युवा पत्रकार सीमा नाज़रेथ की स्मृति में अखबार और नाज़रेथ परिवार द्वारा दिया जाता है, जिसमें 30 वर्ष से कम उम्र के पत्रकार को 50,000 रुपये, चांदी की कलम तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

निर्णायक मंडल ने वीरेश्वर को बिज़नेस स्टैंडर्ड हिंदी में ब्लॉकचेन तकनीक जैसे जटिल और नए विषय से लेकर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर लिखने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। जेल से रिहा कैदियों की जिंदगी पर उनके फीचर लेख से निर्णायक मंडल काफी प्रभावित था।

सीमा नाज़रेथ के पिता पीए नाज़रेथ ने कहा कि संयोग से इस बार का पुरस्कार सीमा के जन्मदिन पर दिया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि देश में सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ता जा रहा है और महात्मा गांधी का बताया अहिंसा का रास्ता ही हमें बचा सकता है।

कम नहीं हो रहा कोरोनावायरस संकट

आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक वृद्धि में कोरोनावायरस का कितना असर होगा इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी

कोरोनावायरस से चीन के जेलों में सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि इससे चीन के हुबेई प्रांत से इतर अन्य हिस्से में संक्रमण मामले की तादाद बढ़ गई है। चीन की जेलों में कोरानावायरस से संक्रमण के 500 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हुबेई प्रांत ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को उसकी जेलों में कोरोनावायरस के 271 मामलों का पता चला।

चीन में जानलेवा वायरस संक्रमण से 118 और मौतें होने से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 2236 हो गई है जबकि संक्रमण के मामले बढ़ कर 75,465 हो गए। इनमें से अधिकतर मामले सर्वाधिक प्रभावित हुबेई प्रांत से हैं। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बाजार में निराशा

संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिका के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशक सोना और सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार में इस बात से भी निराशा बढ़ी जब आंकड़ों से यह अंदाजा मिला कि जापान की फैक्टरियों में फरवरी में सात सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर यह महामारी बढ़ती है तब इसके असर से मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। एशियाई और यूरोपीय शेयरों में गिरावट देखी गई।

> निवेशक सोना व सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्प में कर रहे हैं निवेश

इस सप्ताहांत में सऊदी अरब में 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ी जोखिम पर चर्चा करेंगे। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वैश्विक वृद्धि में कोरोनावायरस का कितना असर होगा इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के 13 नये मामले सामने आए हैं और इन संक्रमित लोगों में से दो की मौत हो गयी है। मंत्रालय ने बताया कि इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है जबकि संक्रमितों की संख्या 18 हो गई है । स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के लोगों का अगले आदेश तक इराक में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। कुवैत एयरवेज ने भी ईरान के लिए अपनी सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

दूसरी ओर, जापान के क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेस से स्वदेश लौटे इजराइल के एक नागरिक में शुक्रवार को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई जो देश का पहला मामला है । कोरोना वायरस से प्रभावित होने के बाद इस जहाज को पृथक रखा गया था। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया, 'क्रूज जहाज से वापस स्वदेश लौटने वाले एक यात्री में इस वायरस की पुष्टि हुई है। उसके नमूने की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला में की गयी थी।' डायमंड प्रिंसेस में सवार इजराइल के 15 यात्रियों को अलग रखा गया था, जिसमें से 11 नागरिक स्वदेश वापस लौट गये हैं।

जापान के तट पर अलग करके खड़े किए गए पोत में कोरोना वायरस से संक्रमित आठ भारतीय नागरिकों की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। इस बीच टोक्यो के पास योकोहामा बंदरगाह पर खड़े पोत 'डायमंड प्रिंसेस' पर सवार स्वस्थ्य लोगों के आखिरी समूह के शुक्रवार को नीचे उतरने की संभावना है। पोत पर यात्री और चालक दल के सदस्यों सहित कुल 3,711 लोग सवार थे। पोत पर कुल 138 भारतीय भी थे जिनमें 132 चालक दल के सदस्य और छह यात्री हैं।

एजेंसियां

पेट्रोकेमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आभूषण निर्माताओं पर संकट के आसार

चीन में फैली कोरोनावायरस महामारी के असर का आकलन करने में सरकार जुटी हुई है। इस बीच क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने घरेलू उद्योग पर इस वायरस संक्रमण के असर के कुछ संकेत दिए हैं। क्रिसिल का मानना है कि वायरस संक्रमण का असर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग स्तर पर दिखेगा। जिन उद्योगों की निर्भरता आयात और निर्यात के लिए चीन पर अधिक है वे ज्यादा प्रभावित होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ उत्पादों के निर्यातकों पर असर होगा मसलन पेट्रोकेमिकल्स और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर असर दिखना लाजिमी है क्योंकि इन उत्पादों के लिए चीन बड़े बाजारों में शामिल है

क्षेत्र	चीन पर निर्भरता	कैसा है असर
एल्युमिनियम	भारत प्राथमिक एल्युमिनियम का एक फीसदी चीन से निर्यात करता है। वहीं कुल मूल्य के 2 फीसदी से कम आयात करता है	ज्यादा उपयोगिता को देखते हुए प्राथमिक एल्युमिनियम निर्यात के लिए अधिक मौके नहीं हैं। आयात में कमी से सेकंडरी एल्युमिनियम कंपनियों को मिलेगा फायदा
वाहन कलपुर्जे	18 फीसदी वाहन कलपुर्जे और 30 फीसदी टायर चीन से आता है	लघु अवधि के लिए इन्वेंट्री पर्याप्त है पर जरूरी एकल पुर्जे की कमी से मूल उपकरण निर्माता कंपनियों की बढ़ेगी मुश्किलें
कृषि से जुड़े उत्पाद	कीटनाशक के लिए भारत कुल तकनीकी इनपुट का 50 फीसदी चीन से आयात करता है जबकि देश में इस्तेमाल होने वाला 10 फीसदी यूरिया वहीं से आयात किया जाता है	अगर विनिर्माण संयंत्रों में इस महीने के आखिर तक संचालन शुरू नहीं होता है तब आगामी खरीफ सीजन के लिए कच्चे माल की खरीदारी में कुछ बाधाएं दिख सकती हैं
सिरैमिक्स	37 फीसदी का आयात चीन से होता है लेकिन आधार बेहद कम है	अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में चीन से होने वाले निर्यात में अस्थायी कमी का फायदा घरेलू कंपनियों को जरूर हो सकता है लेकिन कम क्षमता की वजह से भारत इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (सेलफोन सहित)	भारत 45 फीसदी पूरी तरह तैयार वस्तुओं का आयात करता है वहीं 67 फीसदी जरूरी पुर्जों का आयात भी चीन से किया जाता है	कंपनियों ने अपनी इंवेंट्री बनाए रखी है ऐसे में वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के अंत में इसका असर देखने को मिलेगा। अगले महीने तक उत्पाद की कीमतें बढ़ सकती हैं
रत्न एवं आभूषण	36 फीसदी हीरे का निर्यात चीन में किया जाता है	हॉन्गकॉन्ग इंटरनैशनल ज्वैलरी शो की तारीख में बदलाव आने और कोरोनावायरस से निर्यात पर असर पड़ेगा और इससे वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में घरेलू उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा
पेट्रोकेमिकल	करीब कुल पेट्रोकेमिकल्स का 34 फीसदी चीन भेजा जाता है	इस महामारी की वजह से कीमतें और मार्जिन पर भी दबाव बढ़ेगा
फार्मा बल्क ड्रग	भारत 69 फीसदी फार्मा ड्रग इंटरमीडिएट्स का आयात चीन से करता है	कंपनियों ने चीन की नववर्ष की छुट्टियों की शुरुआत से 2-3 महीने पहले ही कच्चे माल मंगा पर स्टॉक रख लिया था
स्टील	भारत 7 फीसदी स्टील का आयात चीन से करता है	घरेलू स्टील कंपनियों को आयात के बजाय घरेलू उत्पादन से फायदा मिलेगा क्योंकि देशआमतौर पर स्टील जिंस का आयात करता है। कुछ हद तक निर्यात में भी फायदा मिल सकता है क्योंकि वायरस की महामारी से कमी की स्थिति पैदा हो गई है
टेक्सटाइल कॉटन धागे	27 फीसदी कॉटन धागे का निर्यात चीन से किया जाता है	वायरस संक्रमण से घरेलू कॉटन धागे की कीमतों पर दबाव पड़ेगा और इससे कॉटन धागे की कंपनियों को कम मार्जिन मिलेगा
टेक्सटाइल रेडिमेड परिधान	1 फीसदी निर्यात चीन से होता है	लागत बढ़ने की वजह से परिधान उन जगहों से लिया जाएगा जहां लागत कम लगे मसलन भारत। कोरोनावायरस से और मौके बनेंगे

स्रोतः सीआरआईएसआईएल

बड़े विज्ञापनदाताओं की जमात में शामिल गेमिंग ऐप

विवेट सुजन पिंटो

कई सालों की रवायत खत्म होती नजर आई जब वर्ष 2019 में देश के शीर्ष तीन विज्ञापनदाताओं में से कोई खुदरा क्षेत्र या उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़ी कंपनी नहीं बल्कि एक लोकप्रिय गेमिंग ऐप का नाम शुमार किया गया। पिच मैडिसन एडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम 11 नाम के एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ने 2019 में शीर्ष तीन घरेलू विज्ञापनदाताओं में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि पहली बार एक मोबाइल गेमिंग ऐप्लिकेशन इस फेहरिस्त में नजर आई।

रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रीम 11 का विज्ञापन बजट 800 करोड़ रुपये था जबकि एमेजॉन का 900 करोड़ रुपये था। वर्ष 2019 में देश में एमेजॉन दूसरी सबसे बड़ी विज्ञापनदाता कंपनी थी जबकि करीब 3,200 करोड़ रुपये के विज्ञापन बजट के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर शीर्ष कंपनी का तमगा बनाए रखने में कामयाब रही।

विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे और तीसरे बड़े विज्ञापनदाताओं के बीच विज्ञापन खर्च में मामूली अंतर है जिससे एक रोचक रुझान का संकेत मिलता है। यह रुझान विज्ञापन में नई श्रेणियों के उभार का है। दूसरी अहम बात यह है कि ये कंपनियां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं।

फैंटेसी स्पोर्ट्स को ही देखें तो इसके बाजार में वृद्धि हो रही है और नए खिलाड़ियों को आने में मदद मिल रही है। पिछले हफ्ते ट्विटर का समर्थन पाने वाला शेयरचैट, जीत11 के साथ अब फैंटेसी स्पोर्ट्स में प्रवेश करने वाले नए अधिकारी हैं। इसके अलावा इस श्रेणी में कुछ और खिलाड़ी भी हैं मसलन माईटीम11, फैंटेन और स्टारपिक आदि। जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फैंटेसी गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग में मामूली अंतर है हालांकि फैंटेसी गेमिंग का दायरा बड़ा है।

केपीएमजी और इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फैंटेसी गेमिंग मंच के उपयोगकर्ताओं का आधार 7-8 करोड़ तक हो चुका है और इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है क्योंकि क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग को लेकर दर्शकों में दिलचस्पी है और लोग इसे देखना पसंद करते हैं।

अगर विज्ञापन के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ यह है कि इस श्रेणी (फैंटेसी स्पोर्ट्स) के आकार में बढ़ोतरी होगी। मैडिसन वर्ल्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सैम बालसरा के मुताबिक, 'शीर्ष 10 विज्ञापनदाताओं की सूची में फैंटेसी स्पोर्ट्स एकमात्र खिलाड़ी है और आने वाले दिनों में कुछ और भी शामिल हो सकते हैं। डिजिटल क्षेत्र नए विज्ञापनदाताओं को मौके दे रहा है क्योंकि उपभोग और मनोरंजन से जुड़ी आदतें भी बदली हैं।'

ऐसे वक्त में जब उपभोग में कमी आने की वजह से परंपरागत रूप से खर्च करने वाली खुदरा, दूरसंचार, वाहन निर्माता और एफएमसीजी कंपनियां विज्ञापन बजट को लेकर सतर्कता बरत रही हैं, विज्ञापनदाताओं का एक नया समूह इसमें आगे आ रहा है जिससे भविष्य में एक बड़ा अंतर दिखेगा।

ग्रुप एम साउथ एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार कहते हैं, 'वर्ष 2020 में भारत दूसरे बाजारों की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। हालांकि इससे नए दौर के विज्ञापनदाताओं के लिए अपार मौके हैं कि वे नए प्रयोग करें। नई तकनीक और सामग्री के ज्यादा इस्तेमाल से यह रुझान बढ़ेगा।'

ग्रुप एम का कहना है कि ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसी श्रेणियों में तेजी आएगी जिनमें विज्ञापन और सबस्क्रिप्शन आधारित फीड भी शामिल है जिससे वृद्धि होगी। ग्रुप एम का कहना है कि नतीजा यह होगा कि सामग्री और दर्शकों को लेकर होड़ बढ़ेगी।

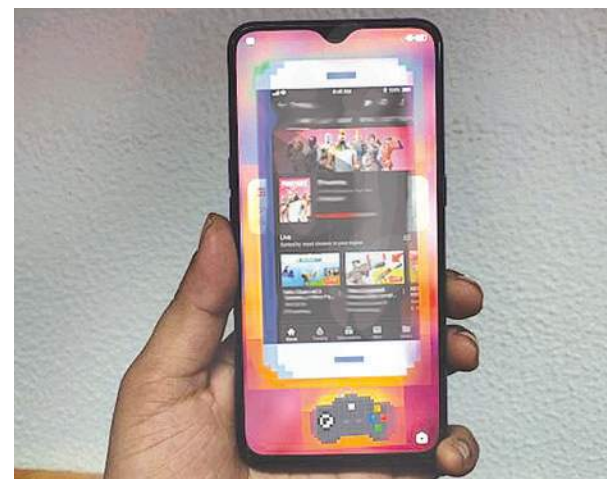

2019 में शीर्ष पांच विज्ञापनदाता

(* आंकड़े रुपये करोड़ में)

कंपनी	* विज्ञापन बजट	2019 में रैंक	2018 में रैंक
हिंदुस्तान यूनिलीवर	3,200	1	1
एमेजॉन	900	2	4
ड्रीम 11	800	3 (नई कंपनी)	मौजूद नहीं
रिलायंस इंडस्ट्रीज	750	4	7
मारुति सुजूकी	700	5	5

स्रोतः पिच मैडिसन रिपोर्ट/उद्योग